

नई दिल्ली
शुक्रवार
18 सितंबर 2026
वर्ष: 13, अंक: 15
पृष्ठ: 08, मूल्य 2 रु0
E-mail
story@sadbhawna.today
sadbhavnatoday@gmail.com
web: www.sadbhawna.today

सोनपुर में उपमुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने की...पेज-05

एक नजर

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोस अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्रियों ने मोदी को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई पक्ष विपक्ष नेताओं ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति मुर्मु ने एक्स पर लिखा, “प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। विगत 25 वर्षों में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के कार्यकाल में आपने सुशासन के अनेक नए प्रतिमान स्थापित किए हैं तथा समावेशी विकास को अभूतपूर्व गति एवं नई दिशा प्रदान की है। सांस्कृतिक गौरव की भावना के साथ आधुनिक प्रगति के मार्ग पर चलते हुए हमारे देशवासी, विरासत और विकास के समन्वय को साकार कर रहे हैं। मैं ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की प्रार्थना करता हूँ, ताकि आप जन-सेवा और राष्ट्र-निर्माण के अपने अभियान को निरंतर आगे बढ़ाते रहें। उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दृढ़ और दूरदर्शी नेतृत्व में, भारत दुनिया में एक घमकते हुए सितारे और सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभर रहा है। 25 करोड़ से ज्यादा भारतीय घोर गरीबी से बाहर निकले हैं। एक क्रांतिकारी डिजिटल क्रांति ने लाखों लोगों को सशक्त बनाया है, और अंतरिक्ष, टेक्नोलॉजी और हेल्थटेकएर से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर और मैनुफैक्चरिंग तक हर क्षेत्र में जबरदस्त विकास हुआ है। पिछड़े जिलों को ‘आकाशी जिले’, सीमावर्ती गाँवों को ‘वाइब्रेंट और पहले गाँव’ और नॉर्थ-ईस्ट को ‘अटलरक्षी’ कहना आपकी दूरदर्शी सोच को दर्शाता है। इस सोच ने भौगोलिक रूप से पिछड़े इलाकों को सशक्तिकरण में बदल दिया है, जिससे ‘विकसित भारत’ की हमारी यात्रा में अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों की सक्रिय भागीदारी संभव हो पाई है। बिरला ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत आज आत्मविश्वास के साथ वैश्विक पटल पर अपनी नई पहचान बना रहा है। विकास, आत्मनिर्भरता, नवाचार, डिजिटल प्रगति, बुनियादी ढाँचे के विस्तार और जनकल्याण की दिशा में देश निरंतर नए आयाम स्थापित कर रहा है।

केंद्र ने पेट्रोल, डीजल और एटीएफ के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स घटाया, नई दरें लागू

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर (विंडफॉल) टैक्स में कटौती की है। नई दरें लागू हो गई हैं। वित्त मंत्रालय ने जारी एक अधिसूचना में कहा कि 16 सितंबर से शुरू हुए पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर (विंडफॉल) टैक्स में कटौती की गई है। शुल्क की नई दरें प्रभावी हो गई हैं। मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक डीजल के निर्यात पर रुपये एवं बुनियादी ढांचा उपकरण समेत विशेष अतिरिक्त उपाद शुल्क (एसएईडी) की दर अब 25 रुपये से घटाकर 20 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। वहीं, विमान ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर एसएईडी 19 रुपये से घटाकर 15 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। इसी तरह पेट्रोल के निर्यात पर शुल्क घटाकर 0.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है, जो पिछले पखवाड़े में 1.5 रुपये प्रति लीटर था। मंत्रालय ने यह भी कहा कि घरेलू स्र्पात वाले पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

सरदार पटेल की बढौलत ही एक सशक्त व एकीकृत ‘एक भारत’ की नींव रखी गयी: सी.पी. राधाकृष्णन

हैदराबाद, एजेंसी। उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने गुरुवार को कहा कि स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के भारत संघ में विलय में देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने असीधारण जिम्मेदारी निभाई और एक सशक्त व एकीकृत ‘एक भारत’ की नींव रखी। सरदार पटेल के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण ही ‘एक भारत’ हमेशा के लिए ‘एक भारत’ रहेगा। यह बात उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने आज यहां सिकंदराबाद स्थित परेड ग्राउंड में केंद्र सरकार द्वारा आयोजित ‘हैदराबाद मुक्ति दिवस’ समारोह के संबोधित करते हुए कहा। यह कार्यक्रम 17 सितंबर 1948 को तत्कालीन हैदराबाद रियासत के भारतीय संघ में औपचारिक विलय

हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

सद्भावना रुडे

आवाज़ अधिकार की

DELHIN/2014/58158

भारत ने अफगानिस्तान को तीसरे टी-20 में...पेज-06

मोदी ने सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन किया

सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण के लिए 13.5 अरब डॉलर की घोषणा की



नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देश में सेमीकंडक्टर तंत्र का तेजी से विस्तार हो रहा है और स्वदेशी चिप अब देश और दुनिया के ग्राहकों तक पहुंचने लगी है। मोदी ने गुरुवार को यहां सेमीकॉन इंडिया 2026 के पांचवें संस्करण का उद्घाटन किया और कहा कि सेमीकंडक्टर क्षेत्र के दिनों दिन बढ़ने से देश में नवाचार, निवेश और विकास के नए अवसर खुल रहे हैं। उन्होंने युवाओं और उद्योग जगत से इस सेमीकंडक्टर मिशन से जुड़ने का आह्वान किया। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत की बढ़ती क्षमता का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने मिशन के दूसरे चरण के लिए 13.5 अरब डॉलर की योजना की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में शुरू हुई सेमीकॉन इंडिया की यात्रा अब नीति और योजना से आगे बढ़कर पायलट लाइन से होते हुए वाणिज्यिक उत्पादन तक पहुंच गई है। मोहाली और सूरत में दो नए संयंत्रों में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर का पूरा तंत्र विकसित करने के लिए चिप डिजाइन, उपकरण निर्माण और परीक्षण की क्षमता जरूरी है। उन्होंने फैबलेस कंपनियों (काफी कम कर्मचारियों वाली कंपनियों), बौद्धिक संपदा और सिलिकॉन फोटोनिक्स पर जोर दिया।

उन्होंने उपकरण, रसायन, गैस और सामग्री क्षेत्र की कंपनियों से 12 स्वीकृत परियोजनाओं और

दिशा सालियान के पिता ने आदित्य ठाकरे और अनिल देशमुख को मेजा 500 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस

मुंबई, एजेंसी। सेलेब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान ने अपनी बेटी की मौत के संबंध में कथित बयानों को लेकर शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 500 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस भेजा है। श्री सालियान नोटिस में दोनों नेताओं से सात दिनों में बिना शर्त लिखित और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है और कहा है कि ऐसा नहीं करने पर दीवानी और आपराधिक मानहानि की कार्यवाही शुरू की जाएगी। नोटिस के अनुसार श्री सालियान ने आरोप लगाया है कि श्री ठाकरे ने उनकी बेटी के लिए न्याय की मांग करने के उनके अभियान को राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित बनाने और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। नोटिस में कथित बयानों को गलत, निराधार और मानहानिकारक बताया गया है। इसमें कहा गया है कि इन बयानों से अपनी बेटी की मौत से जुड़े आरोपों की

कानूनी जांच की मांग कर रहे शोकाकुल पिता की निष्ठा और मंशा पर सवाल उठते हैं। नोटिस में कथित तौर पर किए गये इस दावे पर भी आपत्ति जताई गई है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) पहले ही मामले की जांच कर चुका है और ठाकरे को क्लीन चिट दे चुका है। नोटिस में दो सितंबर को बंबई उच्च न्यायालय में हुई कार्यवाही का उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि सीबीआई ने स्पष्ट किया था कि उसने इस मामले में पहले कोई जांच नहीं की थी। नोटिस में 23 मार्च 2025 को देशमुख के कथित बयान का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें उन्होंने दिशा सालियान मामले को श्री ठाकरे को बदनाम करने की साजिश बताया था। श्री सालियान ने प्रमुख प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल मंचों पर बिना शर्त माफी प्रकाशित करने के साथ-साथ संबंधित आधिकारिक सोशल मीडिया खातों पर कम से कम तीन मिनट का वीडियो जारी कर माफी मांगने की मांग की है।

तमिलनाडु की धरती पर हिंदी नहीं पढ़ाई जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, एजेंसी। उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार से कहा कि हिंदी को लेकर आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है। जस्टिस बीवी नागरला की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि तमिलनाडु की धरती पर हिंदी नहीं पढ़ाई जाएगी।उच्चतम न्यायालय ने चेन्नई और दिल्ली को एक-दूसरे से अलग-थलग करने की सोच पर भी सवाल उठाया। न्यायालय ने कहा कि चेन्नई में बैठे लोगों को दिल्ली में बैठे लोगों से अलग नहीं होना चाहिए और न ही दिल्ली को चेन्नई से।

कोर्ट ने ये टिप्पणी तमिलनाडु सरकार की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान की। तमिलनाडु सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें हर जिले में नवोदय विद्यालय शुरू करने का आदेश दिया गया था। राज्य सरकार का कहना है कि नवोदय विद्यालयों की व्यवस्था उसकी शिक्षा और भाषा नीति से मेल नहीं खाती।इसके पहले 15 दिसंबर 2025 को उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को

आवाज़ अधिकार की

DELHIN/2014/58158

भारत ने अफगानिस्तान को तीसरे टी-20 में...पेज-06

अन्नपूर्णा योजना पश्चिम बंगाल की महिलाओं के आत्मविश्वास को मजबूती देने का महत्वपूर्ण प्रयास : मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि अन्नपूर्णा योजना बंगाल की महिलाओं के आत्मविश्वास को मजबूती देने का महत्वपूर्ण प्रयास है। योजना के तहत करोड़ डेढ़ करोड़ महिलाओं के बैंक खातों में गुरुवार को चौथी क्रिस् पहुंचाई जा रही है। प्रत्येक लाभार्थी महिला को हर महीने 3,000 रुपये मिलेंगे, जिससे उन्हें परिवार के जरूरी खर्चों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि घर में माताओं और बहनों के कंधों पर अनेक जिम्मेदारियां होती हैं। जब जरूरी खर्चों की चिंता कम होती है तो उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। अन्नपूर्णा योजना इसी सोच के साथ बंगाल की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि योजना की राशि सीधे महिलाओं के बैंक खातों में पहुंच रही है, इसलिए उन्हें इसके लिए किसी से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि योजना में न कोई ‘कटमनी’ है और न कोई बिचौलिया। मोदी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि एक भी पात्र महिला अन्नपूर्णा योजना के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि बंगाल की महिलाओं के पास अपने फैसले लेने की ताकत और आगे बढ़ने का बैसला होना चाहिए तथा इसमें अन्नपूर्णा योजना की बड़ी रोलिका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि माताओं, बहनों और बेटियों के जीवन से जुड़ी विविन्न जरूरतों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें गर्भावस्था के दौरान पोषण के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, बेटियों की सुरक्षा और शिक्षा के लिए बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, रक्तेजगार के लिए मुद्रा योजना, उज्ज्वला योजना, हर घर जल, सौभाग्य, आयुष्मान भारत और जनधन योजना शामिल हैं।

अनुसंधान से जुड़े हैं वे आगे आएँ। जो युवा विदेशों में अनसंधान कर रहे हैं वे भी भारत में उन्नत प्रौद्योगिकी के विकास से जुड़ें।’ उन्होंने प्रमुख उद्योगपतियों का आह्वान, ‘मैं उद्योग जगत से आग्रह करता हूं। आप देश में अनुसंधान और विकास के लिए आगे आएँ। इसमें उद्योगों का भी फायदा है और भारत की युवाशक्ति को भी इससे ताकत मिलेगी।’ श्री मोदी ने कहा कि कृत्रिम बुद्धमत्ता (एआई) की बढ़ती मांग से सेमीकंडक्टर क्षेत्र की जरूरतें बदल रही हैं। अब केवल ट्रांजिस्टर के आकार पर ध्यान नहीं है, बल्कि मेमोरी की जगह और गर्मी के प्रबंधन समेत पूरे सिस्टम के एकीकरण पर भी जोर है। उन्होंने कहा कि भारत इन नई वैश्विक विनिर्माण जरूरतों के लिए लगातार तैयारी कर रहा है। उन्होंने एआई डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर संयंत्रों के लिए लगातार बिजली की जरूरत का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 160 गीगावाट से अधिक हो गई है। साथ ही परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोलने और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित करने की दिशा में काम हो रहा है।

भूपेन्द्र यादव की फिनलैंड की मंत्री से मुलाकात, जलवायु सहयोग बढ़ाने पर हुई चर्चा

नई दिल्ली। केन्द्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने गुरुवार को फिनलैंड की जलवायु एवं पर्यावरण मंत्री सारी मुत्ताला से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की गई। बैठक के बाद भूपेन्द्र यादव ने एक्स पोस्ट में कहा कि भारत और फिनलैंड ने सकुलर इकोनॉमी, जलवायु कार्रवाई, जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। नई दिल्ली में फिनलैंड की जलवायु एवं पर्यावरण मंत्री सारी मुत्ताला के साथ द्विपक्षीय बैठक में इन मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ। बैठक में हाल ही में संपन्न वर्ल्ड सकुलर इकोनॉमी फोरम के प्रमुख निष्कर्षों पर चर्चा की गई। साथ ही सकुलर इकोनॉमी के क्षेत्र में भारत-फिनलैंड साझेदारी को आगे बढ़ाने के तरीकों पर विचार किया गया।

मतदान के दौरान व परिणाम आने तक किसी भी संभावित हिंसक झड़प को रोकने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन और दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। नाथं और साउथ कैम्पस के संवेदनशील इलाकों, प्रमुख फैकल्टी और कॉलेजों के बाहर भारी पुलिस बल और बैरिकेडिंग तैनात की गई है। शांति व्यवस्था बनाए रखने और आचार संहिता



निर्देश दिया था कि वो राज्य में नवोदय विद्यालयों की स्थापना के लिए केंद्र के साथ मिलकर भूमि की पहचान करे। कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से कहा था कि आप राज्य में नवोदय विद्यालयों की स्थापना के मुद्दे को भाषा विवाद के बाहर भारी पुलिस बल के तहत सुनवाई के दौरान तमिलनाडु सरकार ने कहा था कि नवोदय विद्यालय तीन भाषा फार्मूला अपनाते हैं, जबकि तमिलनाडु में कानूनी रुप से दो भाषा

आवाज़ अधिकार की

DELHIN/2014/58158

नरेंद्र मोदी ने नक्सलवाद से मुक्ति दिलाई, जम्मू-कश्मीर से हटाया अनुच्छेद 370: राजनाथ

वाराणसी,एजेंसी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि भविष्य में जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विरासत लिखी जाएगी तो उसमें नक्सलवाद से निपटने, जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने, करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने, संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और युवाओं के सपनों को अवसर देने का भी उल्लेख होगा। उन्होंने कहा कि महान नेता लोगों को स्वावलंबी बनाता है और प्रधानमंत्री मोदी ने इसी दिशा में काम किया है। राजनाथ सिंह वाराणसी के सिगरा स्थित रक्षाक्ष कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन और सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ वाराणसी से गुजरात के वडनगर तक आयोजित ‘सेवा संकल्प बाइक यात्रा’ को हरी झंडी दिखाकर खाना किया। राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि काशी और वडनगर को जोड़ने वाली यह यात्रा प्रधानमंत्री की जन्मभूमि को उनकी कर्मभूमि से जोड़ने वाली यात्रा है। एक ओर काशी है, जहां से उनके सार्वजनिक जीवन को नई ऊर्जा मिली, जबकि दूसरी ओर वडनगर है, जहां उन्हें मां हीराबेन के संस्कार और आशीर्वाद मिले। उन्होंने इसे सेवा, संस्कार और साधना के संगम की यात्रा बताया। रक्षा मंत्री ने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि 2014 से पहले भारत के हाथ से कई अवसर निकल जाते थे। उन्होंने दावा किया कि तत्कालीन सरकारों को अपनी कुर्सी बचाने की चिंता रहती थी। सेमीकंडक्टर उद्योग का जिक्र करते

हुए उन्होंने कहा कि दुनिया की एक बड़ी चिप निर्माता कंपनी भारत में फैक्टरी लमाना चाहती थी, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने उसे दो बार अनुमति नहीं दी, जिससे देश ने रोजगार का बड़ा अवसर खो दिया। राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी की स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री दुनिया के बड़े नेताओं से मुलाकात के दौरान उन्हें भारत में बने उत्पाद उपहार में देते हैं। उन्होंने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन को वाराणसी की गुलाबी मीनाकारी से बना पिर्कांन ब्रोच दिए जाने का भी जिक्र किया। कार्यक्रम के दौरान राजनाथ सिंह ने उपस्थित लोगों से मोबाइल फोन की टॉच जलाकर प्रधानमंत्री मोदी की जन्मदिन की बधाई देने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि काशी से वडनगर तक की यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की सार्वजनिक सेवा यात्रा को स्मरण करने का अवसर है।

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव प्रचार थमा, आज मतदान, शनिवार को मतगणना



का उल्लंघन रोकने के लिए पुलिस लगातार गश्त कर रही थी। प्रचार के अंतिम दौर में झड़प की घटनाओं को लेकर पुलिस की जांच तेज हो गई है। प्रॉक्टर कार्यालय परिसर में बीते दिन कथित तौर पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं द्वारा अभाविप सदस्यों पर किए गए कथित हमले के मामले में पुलिस गहन जांच पड़ताल कर रही है। जांच अधिकारी प्रॉक्टर कार्यालय और आसपास के रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रहे हैं, ताकि उपद्रवियों और हमलावरों की स्पष्ट पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। खुले प्रचार पर पाबंदी लगने के बाद छात्र संगठनों ने हॉस्टलों और पीजी (पेइंग

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दिल्ली में एसआईआर का मामला

नई दिल्ली। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का मामला भी उच्चतम न्यायालय पहुंच गया है। आज वकील प्रशांत भूषण ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेशन करते हुए कहा कि दिल्ली में एसआईआर के दौरान पहले ही 47 लाख मतदाताओं के नाम झूफट मतदाता सूची के बाहर कर दिया गया था। अब निर्वाचन आयोग ने तार्किक विसंगति के तहत 33 लाख लोगों को नोटिस जारी किया है। प्रशांत भूषण ने कहा कि ये पूरी प्रक्रिया ही अस्पष्ट है। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि इस याचिका पर 21 सितंबर को सुनवाई होगी जब एसआईआर से जुड़े बाकी राज्यों के मामले पहले से लिस्ट हैं। मेशनिंग के दौरान प्रशांत भूषण ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने किस आधार पर वोटर लिस्ट से नाम काटा है इसका खुलासा नहीं किया है जबकि इसका खुलासा निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर करने का नियम है।

नीति लागू है। इस पर कोर्ट ने कहा था कि आप भाषा को मुद्दा मत बनाइए। हम एक संघीय व्यवस्था में हैं और आप गणराज्य का हिस्सा हैं। यह एक संघीय चर्चा का विषय है और राज्य पर कुछ भी थोपने की बात नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि उसका आदेश तमिलनाडु के ग्रामीण छात्रों के हित में हैं, जो इन विद्यालयों में दाखिले के हकदार हैं।सुनवाई के दौरान तमिलनाडु सरकार ने कहा था कि केंद्र सरकार पर समग्र शिक्षा अभियान के तहत तीन हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि बकाया है। कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को सुझाव दिया था कि वो केंद्र से विचार-विमर्श के दौरान अपनी शर्तें रख सकती हैं जिनमें दो भाषा नीति का पालन और वित्तीय बकाया राशि का भुगतान शामिल हो सकता है।

विजय चौक पर ‘ आशीर्वाद का दीया ’, एनडीएमसी ने जलाए 1.25 लाख दीये

सैफुल्लाह सिद्दीकी, वरिष्ठ पत्रकार

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिवस के अवसर पर नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (एनडीएमसी) ने 17 सितंबर को ‘सेवा दिवस’ के रूप में मनाते हुए नई दिल्ली के विजय चौक पर ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान कर्तव्य पथ से सेवा तीर्थ तक 1.25 लाख मिट्टी के दीये प्रज्वलित किए गए। ‘आशीर्वाद का दिया’ कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय राज्य मंत्री एवं दिल्ली की मुख्ममंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय राज्य मंत्री एवं दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा, नई दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज, एनडीएमसी अध्यक्ष मनोज कुमार द्विवेदी, उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल, एनडीएमसी परिषद् सदस्य दिनेश प्रताप सिंह, एनडीएमसी सचिव राहुल सिंह सहित हजारों एनडीएमसी कर्मचारी, विद्यार्थी एवं शिक्षक उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के 140 करोड़ नागरिकों की निरंतर सेवा की है। उनके जन्मदिवस पर हम सभी भारतीय उनकी सेवाओं के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उन्हें केवल अपना आशीर्वाद दे सकते हैं। ऐसा आशीर्वाद, जिसमें उनकी दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और निरंतर ऊर्जावान जीवन की कामना निहित है।

उन्होंने कहा कि सभी की यही कामना है कि प्रधानमंत्री जी स्वस्थ रहें और इसी प्रकार निरंतर देश की सेवा करते हुए भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ाते रहें तथा राष्ट्र निर्माण में हम सभी का मार्गदर्शन करते रहें। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज कर्तव्य पथ पर, सेवा तीर्थ के बाहर जिस प्रकार दिल्लीवासियों ने अपने घरों से ‘आशीर्वाद का एक



दीया’ जलाया, वह प्रधानमंत्री जी के प्रति जनमानस के स्नेह, सम्मान और विश्वास की सुंदर अभिव्यक्ति है। उन्होंने दिल्ली की जनता का कोटि-कोटि धन्यवाद करते हुए कहा कि नागरिकों ने अपने आशीर्वाद के माध्यम से न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी हैं, बल्कि निरंतर कार्य करने वाली सरकार और ऐसे नेतृत्व को भी अपना आशीर्वाद दिया है, जिसने बिना रुके और बिना थके देश की सेवा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी को कोटि-कोटि नमन करता है।

मालवीय नगर अग्निकांड के दो आरोपितों की न्यायिक हिरासत बढ़ी

नई दिल्ली। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने मालवीय नगर अग्निकांड के मामले के दो आरोपितों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दिया है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भातु प्रताप सिंह ने दोनों आरोपितों की न्यायिक हिरासत 24 सितंबर तक बढ़ाने का आदेश दिया।

आज सुनवाई के दौरान इस मामले के तीनों आरोपित कोर्ट में पेश हुए। होटल मालिक लवकेश बजाज और होटल के मैनेजर जय मिश्रा पित्तहाल केसिक हिरासत में हैं, जबकि कुक न्यास नेगी को जमानत मिल चुकी है। साकेत कोर्ट ने 27 जुलाई को केसर नेगी को जमानत दी थी। इस मामले में कोर्ट ने 3 सितंबर को दिल्ली पुलिस की ओर से तीनों आरोपितों के खिलाफ दायर चार्जशीट पर सज़ा न लिया था। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 1 सितंबर को

चार्जशीट दाखिल किया था। दिल्ली पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 326(जी), 324(5), 125 और 287 के तहत आरोप लगाया था। दिल्ली पुलिस ने लवकेश बजाज को 4 जून को और केसर नेगी को छह जून को गिरफ्तार किया था। आठ जून को जय मिश्रा ने भी कोर्ट में सरेंजर किया था। बताया जा रहा है कि होटल में आग कुक केशव नेगी की लापरवाही की वजह से फैला। आग लगने के बाद केशव नेगी खुद को बचाने के लिए भाग गया। पुलिस के मुताबिक केशव नेगी इलेक्ट्रिक स्टोव पर खाना बना रहा था तभी उसमें ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट के बाद नेगी ने पावर सप्लाई बंद कर दी जिससे होटल के इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे बंद हो गए और कई लोग होटल के अंदर ही फंसे रह गए।

एमसीडी ने सभी 12 जनों में ‘स्वच्छता ही सेवा 2026’ अभियान की शुरुआत की

शबाना बेगम, सद्भावना टुडे
नई दिल्ली। नगर निगम दिल्ली (एमसीडी) ने आज शहर के सभी 12 जनों में ‘स्वच्छता ही सेवा 2026’ अभियान की शुरुआत की। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर, 2026 तक चलने वाले इस मासव्यापी अभियान का उद्देश्य स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को मजबूत करना, स्रोत पर कचरा पृथक्करण को बढ़ावा देना, सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता में सुधार करना तथा स्वच्छता संबंधी पहलों में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।

आज आयोजित विभिन्न गतिविधियों के तहत सेंट्रल जोन द्वारा करमपुरा वार्ड में सफाई कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। पूर्वी जोन के वार्ड 214, आजाद नगर स्थित मलेरिया कार्यालय में स्वच्छता गतिविधियां आयोजित की गईं, जबकि हेडोवार् अस्पताल, विश्वास नगर में मलेरिया कर्मचारियों ने स्वच्छता की शपथ ली। इसके अलावा, ओखला डंपसाइट पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों और स्थानीय निवासियों को वहां चल रहे बायोमाइनिंग एवं बायोमेनेडिशन कार्यों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में लगभग 50 लोगों ने भाग लिया, जिनमें जोन की वार्ड समिति के अध्यक्ष भी शामिल रहे। पश्चिमी जोन में स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान पर केंद्रित वार्ड समिति की बैठक भी आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य



अभियान के प्रति अधिक जागरूकता और भागीदारी सुनिश्चित करना था। बैठक के माध्यम से जनभागीदारी की और मजबूत करने तथा जनप्रतिनिधियों को आरडब्ल्यूए, एमटीए और आम नागरिकों के साथ समन्वय कर स्वच्छता संबंधी गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। अभियान के दौरान एमसीडी द्वारा ‘सफाई मित्र सुरक्षा एवं सम्मान शिविर’, बाजारों, सार्वजनिक स्थलों, झुग्गी बस्तियों, अस्पतालों, पार्कों, डीएमआरसी स्टेशनों, बस स्टेशनों तथा रेलवे पटरियों के आसपास विशेष स्वच्छता अभियान चलाए जाएंगे। इसके अलावा, चिन्हित क्लीनलिनेस टारगेट यूनिट्स को स्वच्छ एवं बेहतर बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। अभियान के तहत चार-तरफा स्रोत पृथक्करण, होम कम्पोस्टिंग, कचरे का जिम्मेदारीपूर्वक

उन्होंने दिल्ली के प्रत्येक घर से जलाए गए ‘आशीर्वाद के दीये’ के लिए दिल्लीवासियों का हृदय से आभार व्यक्त किया। हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस विशेष महत्व रखता है, क्योंकि उनके सार्वजनिक जीवन में राष्ट्रसेवा के 25 वर्ष पूर्ण हुए हैं। इसी विशेष अवसर पर देशभर के लोग उन्हें अपनी शुभकामनाएं और शुभाशीष देने के लिए ‘आशीर्वाद का दिया’ जला रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह दीया देशवासियों के स्नेह, सम्मान और प्रधानमंत्री के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। मल्होत्रा ने कहा कि वे प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रधानमंत्री जी को दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और निरंतर राष्ट्रसेवा के लिए ऊर्जा प्रदान करें, ताकि वे इसी समर्पण के साथ देश को विकसित भारत के संकल्प की दिशा में आगे बढ़ाते रहें। इस अवसर पर नई दिल्ली सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि प्रधानमंत्री का आज मनाया जाने वाला जन्मदिन इस मायने में महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी वर्ष उनके राष्ट्रीय सेवा में निरतुर कार्य करते हुए उनको 25 वर्ष भी पूर्ण हो रहे हैं। उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन मां भारती के के लिए समर्पित किया हुआ है , उन्हें आज आशीर्वाद के दिए से देशवासी और खासकर दिल्लीवासी उनकी स्वस्थ, कर्मशील दीर्घायु की कामना करते हुए विजय चौक पर एकत्र हुए , उसके सभी का आभार है। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी के कार्यकाल में विजय चौक के चारों ओर जो नई संसद , सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवनों का निर्माण हुआ है , वह केवल इमारतों का ही निर्माण नहीं है अपितु विकसित भारत की ओर एक अग्रसर कदम है। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के अध्यक्ष मनोज कुमार द्विवेदी ने कहा कि

अभाविप कार्यकर्ता के घर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के हमले का आरोप, एक हिरासत में

नई दिल्ली,एजेंसी। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव के बीच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) के कार्यकर्ताओं पर बुधवार को उनके एक कार्यकर्ता के आवास पर सुनियोजित तरीके से हमला करने का गंभीर आरोप लगाया है। अभाविप का दावा है कि कार्यकर्ताओं ने मौके से भाग रहे एक हमलावर को पकड़कर स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया, जिसने कथित तौर पर एनएसयूआई का सोशल मीडिया कार्यकर्ता होने की बात स्वीकार की है।

अभाविप के अनुसार यह घटना विश्वविद्यालय क्षेत्र के हरि मंदिर स्थित अभाविप कार्यकर्ताओं के निवास पर हुई। संगठन का कहना है कि आवास पर छात्र कार्यकर्ताओं के साथ छात्राएं भी मौजूद थीं और सभी मिलकर शांतिपूर्ण बैठक कर रहे थे। परिषद का आरोप है कि बिना किसी उकसावे के

सेवा दिवस के अवसर पर विजय चौक पर एक साथ सवा लाख दीयों का प्रज्वलन सेवा, समर्पण और राष्ट्र निर्माण की भावना का प्रतीक बना। इन दीयों की रोशनी ने सेवा के संकल्प को और मजबूत करते हुए देशवासियों को विकसित भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि इन दीयों को प्रज्वलित करने के लिए एनडीएमसी के अधिकारी, कर्मचारी और अन्य सहभागी सेवा भाव के साथ एकजुट हुए। यह सामूहिक प्रयास केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि कर्तव्य, सेवा और जनकल्याण के प्रति प्रतिबद्धता का संदेश है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस आयोजन से प्राप्त प्रेरणा के साथ एनडीएमसी के अधिकारी एवं कर्मचारी अपने-अपने दायित्वों का पूरी निष्ठा और ऊर्जा के साथ निर्वहन करेंगे तथा सामूहिक प्रयासों से एनडीएमसी क्षेत्र को और अधिक स्वच्छ, हरित, सुंदर, सुरक्षित और समृद्ध बनाने में योगदान देंगे।

इस अवसर नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने कहा कि, ‘आशीर्वाद का दिया’ केवल दीये जलाने का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह उन लोगों की भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम है, जिन्हें अलग-अलग सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ मिला है। चहल ने कहा कि कार्यक्रम में शामिल लाभार्थियों की अपनी-अपनी कहानियाँ हैं। किसी को रोजगार मिला है, किसी को स्वास्थ्य सुविधाओं और मेडिकल कार्ड का लाभ मिला है, तो कई लोग केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। उनके लिए जलाया गया हर दिया खुशी, संतोष, आभार और शुभकामनाओं का प्रतीक है।



बाहर से आए एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने अचानक बैठक पर हमला कर दिया। हमले के तुरंत बाद कई हमलावर मौके से फरार हो गए, जबकि एक व्यक्ति को अभाविप कार्यकर्ताओं ने मौके पर ही रोक लिया और कानून अपने हाथ में लिए बिना पुलिस को सौंप दिया। मामले पर कड़ा ऐतराज जताते हुए अभाविप दिल्ली के प्रदेश मंत्री सार्थक शर्मा ने कहा, ‘लोकतांत्रिक छात्र राजनीति को हिंसा के जरिए दबाने का

द्वारका कोर्ट ने उत्तम नगर होली हत्याकांड के आरोपितों की न्यायिक हिरासत 1 अक्टूबर तक बढ़ाई

नई दिल्ली। दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने उत्तम नगर में होली के दौरान हुई हत्या के मामले के सभी आरोपितों की न्यायिक हिरासत 1 अक्टूबर तक बढ़ाने का आदेश दिया। एडिशनल सेशंस जज सुशांत चंगोड़ा ने ये आदेश दिया।

आज सुनवाई के दौरान इस मामले के सभी आरोपित वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश हुए। सुनवाई के दौरान इस मामले के आरोपितों रफीक और सुहेल ने दस्तावेजों के परीक्षण के लिए समय देने की मांग की। कोर्ट ने इस मांग को मंजूर करते हुए 24 सितंबर तक दो आरोपितों की ओर से दस्तावेजों का परीक्षण कर लेने का आदेश दिया। कोर्ट ने आरोपितों रफीक और सुहेल को 24 सितंबर को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश होने का आदेश दिया। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और शिकायतकर्ता की ओर से 10 अक्टूबर को आरोप तय करने के लिए दलीलें रखने का

कॉमनवेल्थ का मूल्यांकन घोषणापत्रों से नहीं, समाधानों से होना चाहिए : विजेंद्र गुप्ता

शाहनवाज सैफ, सद्भावना टुडे
नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि कॉमनवेल्थ का मूल्यांकन उसके द्वारा अपनाए गए घोषणापत्रों से नहीं, बल्कि इस आधार पर होना चाहिए कि हम किन संस्थाओं को मजबूत करते हैं और क्या समाधान प्रदान करते हैं। यह बात विजेंद्र गुप्ता ने दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में आयोजित 69वें कॉमनवेल्थ संसदीय सम्मेलन में कही। उन्होंने ‘कॉमनवेल्थ के लिए नए नेतृत्व के अवसर: लोकतंत्र और अंतरराष्ट्रीय कानून को मजबूत करने के लिए संसदीय कार्रवाई’ विषय पर सत्र को संबोधित किया। यह जानकारी आज एक बयान में दी गई।

सशस्त्र संघर्ष, भू-राजनीतिक प्रतियर्धा, संस्थाओं में घटते विश्वास, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर गुप्ता ने कहा कि संसदों को ऐसे संस्थानों के रूप में काम करना होगा, जो जनता की चिंताओं और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को कानून, निगरानी और जवाबदेह कार्रवाई में बदल सकें। चुनाव लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार देते हैं, लेकिन लोकतंत्र की वास्तविक मजबूती चुनावों के बीच की अवधि में दिखाई देती है। इसके लिए विधायी समीक्षा, सरकारी खर्च में पारदर्शिता, प्रभावी समितियां और नागरिकों की सार्थक भागीदारी जरूरी है। लगभग 56 देशों वाले कॉमनवेल्थ में दुनिया की लगभग एक-तिहाई आबादी रहती है। इसकी विविधता के कारण

दिल्ली नगर निगम का ध्वस्तीकरण अभियान जारी; 39 ध्वस्तीकरण कार्रवाई की गई



सद्भावना टुडे, संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम ने खतरनाक इमारतों, अनधिकृत निर्माण तथा दिल्ली के मास्टर प्लान और भवन उपविधियों के उल्लंघन के विरुद्ध दिल्ली में व्यापक प्रवर्तन अभियान को जारी रखा है। भवन निर्माण संबंधी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा जन सुरक्षा की दृष्टि से निगम के सभी 12 क्षेत्रों में सख्त प्रवर्तन कार्रवाई की जा रही है। आज चलाए गए गहन प्रवर्तन अभियान के दौरान निगम के सभी 12 क्षेत्रों में 39 ध्वस्तीकरण कार्रवाई की गई। इसके अतिरिक्त, 6 संपत्तियों को सील किया गया, जबकि भवन निर्माण संबंधी नियमों एवं प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर 5 ध्वस्तीकरण आदेश जारी किए गए। नगर निगम द्वारा कल भी व्यापक प्रवर्तन अभियान चलाया गया था, जिसके दौरान दिल्ली के मास्टर प्लान और भवन उपविधियों के उल्लंघन के मामलों में 46 संपत्तियों का ध्वस्तीकरण किया गया तथा 11 संपत्तियों को सील किया गया। आज के प्रवर्तन अभियान के दौरान दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख ध्वस्तीकरण कार्रवाई की गई। इनमें पूर्वी क्षेत्र के शकरपुर, गीता कॉलोनी और पांडव नगर, अशोक विहार चरण-दो, केशवपुरम, रमेश नगर, बलजीत नगर, मानकपुरा, पहाड़गांज, शाहीन बाग, संत नगर तथा तुगलकाबाद विस्तार सहित अन्य क्षेत्र शामिल हैं। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि उसके अधिकार क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अनधिकृत निर्माण अथवा भवन निर्माण संबंधी नियमों के उल्लंघन की अनुमति नहीं दी जाएगी। अनधिकृत निर्माण, खतरनाक इमारतों तथा जन सुरक्षा के लिए जोखिम उत्पन्न करने वाले अन्य उल्लंघनों के विरुद्ध जारी प्रवर्तन अभियान पूरी सख्ती के साथ अगे भी जारी रहेगा। नगर निगम ने संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में कड़ी निगरानी बनाए रखने तथा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यह कार्रवाई दिल्ली के मास्टर प्लान, भवन उपविधियों तथा अन्य लागू नियमों एवं प्रावधानों के अनुसार की जा रही है।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ‘स्वच्छता ही सेवा 2026’ अभियान का शुभारंभ



नई दिल्ली। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजेश कुमार पाण्डेय ने गुरुवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ‘स्वच्छता ही सेवा 2026’ अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने रेल अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में दिल्ली मंडल के मंडल रेल प्रबंधक पुष्पेश रमण त्रिपाठी सहित उत्तर रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। अभियान के शुभारंभ के अवसर पर महाप्रबंधक एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अजमेरी गेट की ओर श्रमदान किया। इस दौरान यात्रियों के बीच स्वच्छता का संदेश पहुंचाने के लिए नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर कहा गया कि यात्रियों में स्वच्छता के संस्कार विकसित करने से स्वच्छ भारत के लक्ष्य को अधिक प्रभावी ढंग से हासिल किया जा सकता है। ‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियान यात्रियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने और उन्हें जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। रेल प्रशासन ने यात्रियों से अभियान में सक्रिय रूप से सहभागिता करने तथा रेलवे परिसर को स्वच्छ रखने में सहयोग देने की अपील की। साथ ही स्वच्छ एवं स्वस्थ भारत के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया।

आतंकी मसूद पर पाकिस्तान की नई नौटंकी

सुरेश हिंदुस्तानी

आतंकवाद के प्रश्न पर पाकिस्तान की भूमिका लंबे समय से विश्व समुदाय के लिए चिंता का विषय रही है। आतंकवाद के विरुद्ध कठोर कार्रवाई का दिखावा और आतंकी संगठनों के प्रति नरम रवैया, पाकिस्तान की विदेश एवं सुरक्षा नीति के इस विरोधाभासी चरित्र ने उसकी विश्वसनीयता को लगातार कठघरे में खड़ा किया है। आतंकी सरगना मसूद अजहर को लेकर पाकिस्तान की हालिया कार्रवाई भी इसी विरोधाभास की एक नई कड़ी के रूप में देखी जा रही है। उसे भगोड़ा घोषित करना और उसकी गिरफ्तारी पर इनाम की घोषणा करना पहली दृष्टि में कठोर कार्रवाई का संकेत देता है, लेकिन पाकिस्तान के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए इसके पीछे की वास्तविक मंशा पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। मसूद अजहर कोई सामान्य अपराधी नहीं है। वह भारत में हुए अनेक आतंकी हमलों से जुड़े उन कुख्यात चेहरों में रहा है, जिनकी गतिविधियों ने न केवल भारत की सुरक्षा को चुनौती दी, बल्कि दक्षिण एशिया में आतंकवाद के नेटवर्क की भयावहता को भी उजागर किया। वर्ष 1999 में इंडियन एयरलाईस के विमान के अपहरण के बाद यात्रियों की रिहाई के बदले भारत को जिन आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा, उनमें मसूद अजहर भी शामिल था। इसके बाद उसने आतंकवादी गतिविधियों के जिस नेटवर्क को आगे बढ़ाया, उसने भारत की सुरक्षा व्यवस्था के सामने गंभीर चुनौतियां खड़ी कीं। विडंबना यह है कि जिस व्यक्ति को भारत लंबे समय से आतंकवाद का प्रमुख चेहरा मानता रहा है, उसी मसूद अजहर को लेकर पाकिस्तान अब यह दावा कर रहा है कि वह उसकी पकड़ से बाहर है और संभवतः अफगानिस्तान में छिपा हुआ है। यदि यह दावा सही है तो सवाल यह उठता है कि पाकिस्तान की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां इतने कुख्यात आतंकी के संबंध में इतनी अनभिज्ञ कैसे हो सकती हैं? और यदि वह पाकिस्तान से बाहर है तो उसके संगठनात्मक नेटवर्क, आर्थिक संसाधनों और संपर्कों पर कार्रवाई क्यों दिखाई नहीं देती? यहीं से पाकिस्तान की कार्रवाई पर संदेह की परतें गहरी होने लगती हैं।

पाकिस्तान की जांच एजेंसी एफआईए द्वारा मसूद अजहर को अपने अत्यंत खतरनाक आतंकवादियों की सूची में शामिल किया जाना अपने आप में महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। लेकिन केवल किसी आतंकी को सूचीबद्ध कर देना आतंकवाद के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई नहीं



माना जा सकता। असली कसौटी गिरफ्तारी, न्यायिक प्रक्रिया, आतंकी नेटवर्क का विघटन और उसके वित्तीय स्रोतों पर प्रभावी प्रहार है। यदि कार्रवाई केवल कागजों तक सीमित रह जाए, तो वह आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय दबाव को टालने की प्रशासनिक कवायद बनकर रह जाती है। भारत के सुरक्षा तंत्र से जुड़े इनपुट यदि यह संकेत देते हैं कि मसूद अजहर पाकिस्तान में ही छिपा हुआ है, तो पाकिस्तान के दावे की विश्वसनीयता और भी संदिग्ध हो जाती है। हालांकि ऐसे खुफिया दावों की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक होती है, लेकिन पाकिस्तान का अतीत उसके वर्तमान दावों पर सहज विश्वास करने की अनुमति नहीं देता। पाकिस्तान का यह दोहरा चरित्र नया नहीं है। दुनिया पहले भी देख चुकी है कि आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई का दावा करने वाला

पाकिस्तान अपनी ही धरती पर छिपे कुख्यात आतंकवादियों की मौजूदगी से लंबे समय तक इनकार करता रहा। ओसामा बिन लादेन का पाकिस्तान में पाया जाना इस संदर्भ में सबसे चर्चित उदाहरण है। अमेरिकी कार्रवाई में एबटाबाद में लादेन के मारे जाने के बाद पाकिस्तान के उन दावों की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न उठे थे, जिनमें वह अपनी धरती पर आतंकवादी सरगनाओं की मौजूदगी से अनभिज्ञता जताता रहा था।

आतंकी मसूद अजहर पर पाकिस्तान सरकार की कार्यवाही को इसलिए भी संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में आतंकी सरगनाओं पर न तो सरकार का नियंत्रण है और न ही सेना की ही चलती है। आतंकियों का अपना एक तंत्र है। जिनमें कोई भी दखल नहीं दे सकता। पाकिस्तान में तीन शक्ति केंद्र माने जाते

हैं, जिनमें सरकार, सेना और आतंकवादी हैं। कई बार यह भी देखने में आता है कि वहां की सरकार किसकी होगी, यह आतंकी और सेना तय करती है। इसलिए सरकार, आतंकियों पर कठोर कार्यवाही करने का सामर्थ्य नहीं जुटा पाती। और आतंकी फलीभूत होते रहते हैं। इस पृष्ठभूमि में मसूद अजहर पर घोषित इनाम को केवल कानून-व्यवस्था की कार्रवाई के रूप में देखना कठिन है। इसके पीछे पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय छवि सुधारने की मंशा भी दिखाई देती है। विशेषकर आतंकवाद के वित्तपोषण और धनशोधन से जुड़े अंतरराष्ट्रीय मानकों के संदर्भ में पाकिस्तान पर लगातार दबाव रहा है। ऐसे समय में किसी कुख्यात आतंकी के विरुद्ध सार्वजनिक कार्रवाई का प्रदर्शन अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को यह संदेश देने का प्रयास हो सकता है कि पाकिस्तान आतंकवाद के विरुद्ध

महंगाई बढ़ने के कारण प्याज (22.54%), लहसुन (35.36%) और अदरक (83.62%) की कीमतों में भारी तेजी आई है। ईंधन और परिवहन महंगाई बढ़कर 4.43% हो गई है, जिससे माल ढुलाई की लागत बढ़ी है। रेस्त्रां और आवास सेवाओं की महंगाई दर बढ़कर लगभग 7.72% हो गई है। देश के आम आदमी को हर दिन होने वाली कठिनाईयों से जूझना पड़ रहा है। देश का मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग को जीडीपी की गोथ से अंतर तब पड़ता है, जब उनकी बुनियादी सुविधाओं कोई बेहतरी नजर आए। देश में पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल, सड़क, रोजगार, महंगाई जैसी बुनियादी समस्याओं की भरमार है। इनसे राहत मिलती भी है तो रूट के मुंह में जीरे जितनी। इससे बदलाव नजर नहीं आता। भारत की आधी से अधिक आबादी यानी करीब 60 करोड़ लोग गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। देश के भूजल का बड़ा हिस्सा आर्सेनिक, प्लोराइड और अन्य भारी धातुओं (हैवी मेटल्स) की वजह से दूषित हो चुका है। बारिश का पर्याप्त पानी होने के बावजूद उचित हार्वेस्टिंग (संचयन) न होने के कारण पानी बेकार बह जाता है। नीति आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, साफ पीने का पानी न मिलने के कारण हर साल देश में करीब 2 लाख लोगों की मौत हो जाती है।

जीडीपी से नहीं जमीन पर नजर आए बदलाव

योगेंद्र योगी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों से भारत की तरक्की का जजन मनाने के लिए कहते हुए 7.8% की शानदार जीडीपी ग्रोथ के लिए बधाई दी। सवाल यह है कि क्या आम आदमी देश में जीडीपी ग्रोथ को समझता है। क्या जीडीपी बढ़ना देश की मौजूदा समस्याओं के समाधान का कोई पैमाना है। देश में जब प्रधानमंत्री जीडीपी बढ़ोतरी की घोषणा कर रहे थे, उसी दिन कमर्शियल एलपीजी के दाम में बढ़ोतरी हो गई है। दिल्ली में इसके दाम में 9.50 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में अब कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2747.50 रुपये, मुंबई में 2701 रुपये और चेन्नई में 2916.50 रुपये हो गई है। कमर्शियल सिलेंडर के महंगे होने से होटल, ढाबे आदि में खाना-पीना महंगा होना तय है। वहीं घर मिलने वाली चीजों के दाम में भी बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा 5 किलो वाले गैस सिलेंडर का भी दाम 2 रुपये बढ़कर 764 रुपये हो गया है। मुंबई और तमिलनाडु में दूध महंगा हो गया है। बॉम्बे मिल्क प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने थोक दूध की कीमतों में 9 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इससे दूध की थोक दर 93 रुपये से बढ़कर 102 रुपये प्रति लीटर हो गई है। भारत में जुलाई-अगस्त 2026 के दौरान खाद्य महंगाई दर बढ़कर 5.52% हो गई है, जिसके कारण चीनी, प्याज, टमाटर, दाल और खाना पकाने के तेल जैसी जरूरी रसोई की चीजें महंगी हो गई हैं. चावल और दूध के दाम भी स्थिर से लेकर उच्च स्तर पर बने हुए हैं। महंगाई बढ़ने के कारण प्याज (22.54%), लहसुन (35.36%) और अदरक (83.62%) की कीमतों में भारी तेजी आई है। ईंधन और परिवहन महंगाई बढ़कर 4.43% हो गई है, जिससे माल ढुलाई की लागत बढ़ी है। रेस्त्रां और आवास सेवाओं की महंगाई दर बढ़कर लगभग 7.72% हो गई है। देश के आम आदमी को हर दिन होने वाली कठिनाईयों से जूझना पड़ रहा है। देश का मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग को जीडीपी की ग्रोथ से अंतर तब पड़ता है, जब उनकी बुनियादी सुविधाओं कोई बेहतरी नजर आए। देश में पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल, सड़क, रोजगार, महंगाई जैसी बुनियादी समस्याओं की भरमार है। इनसे राहत मिलती भी है तो रूट के मुंह में जीरे जितनी। इससे बदलाव नजर नहीं आता। भारत की आधी से अधिक आबादी यानी करीब 60 करोड़ लोग गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। देश के भूजल का बड़ा हिस्सा आर्सेनिक, प्लोराइड और अन्य भारी धातुओं (हैवी मेटल्स) की वजह से दूषित हो चुका है। बारिश का पर्याप्त पानी होने के बावजूद उचित हार्वेस्टिंग (संचयन) न होने के कारण पानी बेकार बह जाता है। नीति आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, साफ पीने का पानी न मिलने के कारण हर साल देश में करीब 2 लाख लोगों की मौत हो जाती है। वर्ष 2026 में भीषण गर्मी, रिकॉर्ड बिजली मांग (मई 2026 में 270 गीगावाट से अधिक) और स्थानीय रख-रखाव के कारण उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, ओडिशा और तेलंगाना जैसे कुछ राज्यों के इलाकों में आंशिक या अस्थायी कटौती की गई।

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बेघरता को दर प्रति 10,000 लोगों पर 13 है। अर्थात 17 प्रतिशत लोगों को पास अपना घर नहीं है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 35 प्रतिशत गांवों में स्थानीय स्तर पर कोई भी बुनियादी चिकित्सा सुविधा या स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध नहीं है। ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों और सर्जनों की भारी कमी है, जो लगभग 80 प्रतिशत तक



खाली पड़े हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले 10 वर्षों (2014–15 से 2024–25) में देश भर में करीब 94,000 सरकारी स्कूल बंद या आपस में मर्ज किए गए हैं। इसका मतलब है कि औसतन हर दिन 25 स्कूलों पर ताला लगा है। इसी दशक में सरकारी स्कूलों में कुल छात्रों का नामांकन 2.26 करोड़ कम हुआ है, जो 2014–15 के 26.95 करोड़ से घटकर 2024–25 में 24.69 करोड़ रह गया है। देश के एक लाख से अधिक स्कूलों में आज भी बिजली की उचित सुविधा नहीं है, और कई स्थानों पर पीने का साफ पानी उपलब्ध नहीं है। 71,959 स्कूलों में लड़कियों के लिए और 1.12 लाख स्कूलों में लड़कों के लिए काम करने वाले शौचालय मौजूद नहीं हैं। 1.39 लाख स्कूलों में लाइब्रेरी और 2.65 लाख स्कूलों में खेल का मैदान नहीं है। डिजिटल लाइब्रेरी का अभाव तो लगभग 13.62 लाख स्कूलों में है। भारत में 15 से 29 वर्ष के युवाओं की बेरोज़गारी दर जून 2026 में बढ़कर 16.2% हो गई है, 15-29 आयु वर्ग की महिलाओं में यह दर बढ़कर 20.7%

हो गई। इसी आयु वर्ग के पुरुषों में यह दर 14.6% दर्ज की गई। जून 2026 में शहरी युवा बेरोज़गारी दर 18.2% और ग्रामीण युवा बेरोज़गारी दर 15.1% रही। नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार, सबसे अधिक गरीबी वाले राज्य बिहार में 51.91% आबादी गरीब है।

झारखंड में 42.16% लोग गरीबी में जीवन बिता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 37.79% जनसंख्या गरीब है। मध्य प्रदेश में 36.65% लोग गरीब हैं। भारत में सबसे अमीर 10% लोगों के पास कुल संपत्ति का लगभग 65% हिस्सा है. सबसे ज्यादा कमाई करने वाले 10% लोग राष्ट्रीय आय का 58% हिस्सा पाते हैं जबकि सबसे निचले 50% लोगों को सिर्फ 15% मिलता है। आर्थिक असमानता की यह खाई लगातार बढ़ती जा रही है। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री का यह हक है कि जीडीपी की ग्रोथ पर खुशी मनाने का आह्वान करं पर जब तक इसका असर देश की मूल समस्याओं के निराकरण में नजर नहीं आएगा, देश के लोगों की उदासी दूर नहीं होगी।

विचार वडनगर से वैश्विक मंच तक नरेंद्र मोदी की राजनीतिक यात्रा

डॉ. ब्रह्मानंद राजपूत

17 सितंबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 76वां जन्मदिन मना रहे हैं। गुजरात के छोटे से शहर वडनगर से शुरू हुई उनकी जीवन-यात्रा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक, भारतीय जनता पार्टी के संगठनकर्ता, गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने तक पहुंची। नरेंद्र मोदी का राजनीतिक जीवन भारतीय राजनीति में लंबे समय तक चर्चा और विश्लेषण का विषय रहा है। उनके समर्थक उन्हें निर्णायक नेतृत्व, विकास योजनाओं और भारत की वैश्विक भूमिका को मजबूत करने वाला नेता मानते हैं, जबकि आलोचक आर्थिक नीतियों, रोजगार और सामाजिक मुद्दों को लेकर सवाल भी उठाते रहे हैं। नरेंद्र दामोदरदास मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर में हुआ। उनका बचपन एक सामान्य परिवार में बीता। युवावस्था में उन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों की यात्राएं कीं और बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े। वर्ष 1972 में वे संघ के प्रचारक बने। आपातकाल के दौर में भी वे राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहे। संगठन के प्रति उनकी कार्यशैली, अनुशासन और व्यापक संपर्क क्षमता ने उन्हें धीरे-धीरे भाजपा के संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों तक पहुंचाया। 1987 में वे भाजपा की गुजरात इकाई में संगठन की भूमिका से जुड़े और 1990 के दशक में पार्टी के राष्ट्रीय संगठन में भी उनकी भूमिका बढ़ती गई। 1998 में वे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बने। 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पद संभाला और मई 2014 तक इस पद पर रहे।

मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में औद्योगिक निवेश, सड़क, बिजली, सिंचाई, शहरी विकास और प्रशासनिक सुधारों पर जोर दिया गया। वर्ष 2003 में गुजरात में ‘वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट’ की शुरुआत हुई, जो आगे चलकर बड़े निवेश और व्यापार सम्मेलन के रूप में विकसित हुआ। गुजरात मॉडल को लेकर जहां संपर्कों ने आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे की उपलब्धियों को रेखांकित किया, वहीं आलोचकों ने विकास के लाभों के समान वितरण और सामाजिक मुद्दों पर भी सवाल उठाए। 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने लोकसभा चुनाव में 282 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया और 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 2019 में भाजपा ने अपना प्रदर्शन और मजबूत करते हुए 303 सीटें जीतीं। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को अकेले बहुमत नहीं मिला, लेकिन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को बहुमत प्राप्त हुआ और नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की एक प्रमुख पहचान बड़े पैमाने पर लागू की गई जनकल्याणकारी योजनाएं, डिजिटल तकनीक और बुनियादी ढांचे का विस्तार रही है। प्रधानमंत्री जन-धन योजना ने बैंकिंग व्यवस्था से बाहर रहे लोगों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ने में भूमिका निभाई। स्वच्छ भारत मिशन ने स्वच्छता और शौचालय निर्माण को राष्ट्रीय अभियान का रूप दिया। उज्ज्वला योजना के माध्यम से गरीब परिवारों की महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं ने आवास, कृषि सहायता, स्वास्थ्य और पेयजल जैसे क्षेत्रों को नीति के केंद्र में रखा। इसी दौर में डिजिटल भुगतान और आधार आधारित सेवाओं का विस्तार भी तेजी से हुआ। यूपीआई ने डिजिटल लेन-देन को आम नागरिकों की रोजमर्रा की आर्थिक गतिविधियों का हिस्सा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, रिकल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों के जरिए विनिर्माण, उद्यमिता, कौशल और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। दूसरी ओर, इन नीतियों के प्रभाव को लेकर रोजगार, छोटे कारोबार, ग्रामीण आय और आर्थिक असमानता जैसे सवाल भी सार्वजनिक बहस में बने रहे। इससे स्पष्ट है कि मोदी सरकार के आर्थिक और कल्याणकारी कार्यक्रमों का मूल्यांकन केवल योजनाओं की संख्या से नहीं, बल्कि उनके वास्तविक और दीर्घकालिक प्रभाव से किया जाना चाहिए। बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भी मोदी सरकार के वर्षों में सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों और डिजिटल नेटवर्क के विस्तार पर विशेष जोर रहा। इन परियोजनाओं ने संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में भूमिका निभाई है। साथ ही, बड़े पैमाने पर सार्वजनिक निवेश की उपयोगिता और उसके क्षेत्रीय वितरण और उससे रोजगार सृजन जैसे प्रश्न भी नीति-विश्लेषण का हिस्सा बने हुए हैं। विदेश नीति के मोर्चे पर मोदी सरकार के दौरान भारत की सक्रियता और वैश्विक प्रभाव दोनों बढ़े। जी-20 और ब्रिक्स जैसे मंचों पर भारत की भूमिका मजबूत हुई, वहीं रूस-यूक्रेन युद्ध से लेकर ईरान-इजरायल संघर्ष और अमेरिका के साथ बदलते संबंधों के बीच भारत ने रणनीतिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश की।

एक नजर

सड़क दुर्घटना में युवक की मौत, शव गांव पहुंचते ही मचा कोहराम



नवादा,एजेंसी। जिले में नारदीगंज थाना क्षेत्र के पड़रिया गांव के समीप गुरुवार को हुई सड़क दुर्घटना में नरहट थाना क्षेत्र के करमा गांव निवासी अभिषेक कुमार (25) की मौत हो गई। शव गांव पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। स्वजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। बताया जाता है कि अभिषेक कुमार अकबरपुर के समीप फतेहपुर बाजार में बर्तन की दुकान चलाता था। तीन पर्व को लेकर वह अपने ससुराल रजौन गया था। बुधवार को वह अपने साले के साथ वापस लौट रहा था। इसी दौरान नारदीगंज के पड़रिया गांव के समीप सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। युवक लगभग दो साल पूर्व शादी हुआ था। अभिषेक की मौत की खबर मिलते ही करमा गांव में चल रहे पूजा के उत्सव का माहौल गम में बदल गया। गांव में पूजा के अवसर पर तीन दिवसीय नाटक का मंचन किया जा रहा था। घटना के बाद नाटक कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया और पूरे गांव में मातम पसर गया। अभिषेक तीन भाइयों में दूसरे नंबर पर था। घटना की जानकारी मिलने के बाद समाजसेवी प्रवीण चंद्रवंशी ने गहरा दुख जताया। उन्होंने शोकाकुल परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी और हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया।

होटल-रेस्टोरेंट समेत खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की मांग

किशनगंज। शहर में संचालित होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, मिठाई दुकान, फास्ट-फूड सेंटर एवं अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों की जांच कराने की मांग उठी है। जिला युवा कांग्रेस कमिटी, किशनगंज के जिलाध्यक्ष मो. आजाद साहिल ने गुरुवार को जिलाधिकारी नवीन कुमार को पत्र लिखकर शहर के खाद्य प्रतिष्ठानों में व्यापक जांच अभियान चलाने का अनुरोध किया है। पत्र के माध्यम से उन्होंने कहा कि किशनगंज शहर में बड़ी संख्या में होटल, रेस्टोरेंट और अन्य खाद्य प्रतिष्ठान संचालित हैं। इन प्रतिष्ठानों में प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं। ऐसे में आम लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की नियमित जांच आवश्यक है। उन्होंने प्रशासन से खाद्य सुरक्षा पदाधिकारियों के माध्यम से प्रतिष्ठानों की जांच कराने की मांग की है। जांच के दौरान खाद्य सामग्री के सुरक्षित भंडारण, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता, रसोईघर की साफ-सफाई, खाद्य पदार्थों को उचित तापमान पर रखने तथा एक्सपायरी डेट वाली सामग्री के उपयोग की भी जांच करने का आग्रह किया गया है। मो. आजाद साहिल ने कहा कि खाद्य प्रतिष्ठानों में स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना जनस्वास्थ्य के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि यह मांग किसी विशेष प्रतिष्ठान को निशाना बनाने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि शहरवासियों की सुरक्षित, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है। उन्होंने नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ प्रचलित कानून एवं नियमों के तहत आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही समय-समय पर ऐसे जांच अभियान चलाते रहने का भी अनुरोध किया है। युवा कांग्रेस कमिटी ने उम्मीद जताई कि जिला प्रशासन इस मामले में शीघ्र संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई करेगा।

किशनगंज में धूमधाम से मनाई गई विश्वकर्मा पूजा

किशनगंज। जिले में गुरुवार को भगवान विश्वकर्मा की पूजा श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक विभिन्न स्थानों पर पूजा पंडाल बनाए गए, जहां सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी। लोगों ने अपने वाहनों, मशीनों, औजारों और दुकानों में भगवान विश्वकर्मा की पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि एवं कारोबार में सफलता की कामना की। किशनगंज शहर के रेलवे कॉलोनी, धरमागंज सहित कई इलाकों में आकर्षक पूजा पंडाल बनाए गए थे। पंडालों को रंग-बिरंगी रोशनी, फूलों और सजावटी सामग्री से सजाया गया था। पूजा स्थलों पर भक्ति गीतों के बीच श्रद्धालु भगवान विश्वकर्मा की आराधना करते नजर आए। ग्रामीण क्षेत्रों में भी विश्वकर्मा पूजा को लेकर खासा उत्साह रहा। परिवार के साथ लोग पूजा स्थलों पर पहुंचे और विधि-विधान से पूजा की। ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, गैराज, परिवहन प्रतिष्ठानों और उद्योगों में भी विशेष आयोजन किए गए। विशेष माफिलकों और चालकों ने ट्रक, बस, ऑटो, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल सहित अन्य वाहनों की साफ-सफाई कर उनकी पूजा की। कई स्थानों पर श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। कुछ जगहों पर भंडारे का भी आयोजन हुआ। पूजा समितियों की ओर से कई स्थानों पर मेले लगाए गए हैं। मेला परिसर में झूले, खाने-पीने की दुकानें और विभिन्न प्रकार के स्टॉल आकर्षण का केंद्र बने रहे। बच्चों और युवाओं की भीड़ भी मेले में पहुंची। पूजा पंडालों और मेला क्षेत्रों में सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। विश्वकर्मा पूजा को लेकर प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता बरती गई।प्रमुख पूजा स्थलों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस बल की तैनाती की गई। संवेदनशील क्षेत्रों में भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। प्रशासन ने पूजा समितियों से सुरक्षा मानकों का पालन करने तथा भीड़ प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की अपील की है।

सोनपुर में उपमुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने की जिला कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक



सारण,एजेंसी। सोनपुर स्थित प्लस टू सेमिनरी हाई स्कूल के सभाकक्ष में आज शाम प्रभारी मंत्री-सह-उपमुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव की अध्यक्षता में जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति 20 सूत्री की बैठक हुई। बैठक में जिले के विभिन्न नगर निकायों के गठन, उत्क्रमण तथा क्षेत्र विस्तार से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। बैठक की शुरुआत से पहले जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव एवं वरीय पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार ने प्रभारी मंत्री का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया, जिसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कार्यवाही के दौरान जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने पूर्व में भेजे गए प्रस्तावों के

साथ-साथ दो नए प्रस्तावों को समिति के समक्ष रखा। इस दौरान प्रस्तावित क्षेत्रों के क्षेत्रफल, जनसंख्या, नजरी नक्शा और भौगोलिक स्थिति की जानकारी साझा की गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि नगर निकायों के मानक हेतु जनसंख्या नगर पंचायत के लिए 12-40 हजार, नगर परिषद के लिए 40 हजार से 2 लाख और नगर निगम के लिए 2 लाख से अधिक, भौगोलिक स्वरूप तथा आजीविका के स्रोतों को मुख्य आधार बनाया गया है।

कुल 15 प्रस्तावों पर हुआ मंथन जिसमें क्षेत्र विस्तार के लिए नगर निगम छपरा एवं नगर परिषद सोनपुर, नगर परिषद में उत्क्रमण के लिए रिविलगंज, मढ़ौरा, परसा एवं दिचवारा नगर

पंचायत तथा नए नगर पंचायत गठन के लिए दरियापुर बेला, तरैया, बनियापुर, इसुआपुर, नगरा, पानापुर, गरखा एवं मकेर को नगर पंचायत तथा अमनौर को नगर परिषद बनाने का प्रस्ताव पर चर्चा हुआ। बैठक में 20 सूत्री समिति के उपाध्यक्ष-सह-सोनपुर विधायक विनय सिंह, तरैया विधायक जनक सिंह, विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह, विधान पार्षद वीरेंद्र नारायण यादव, 20 सूत्री उपाध्यक्ष रंजीत कुमार सिंह , नगर निगम के मेयर लक्ष्मी नारायण गुप्ता सहित सभी जिला व अनुमंडल स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। इन प्रस्तावों की स्वीकृति से जिले में नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के विकास को गति मिलने की उम्मीद है।

नाथनगर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की मारी कमी, समी पीड़ितों को मिले जीआर की राशि: जेड हसन

भागलपुर,एजेंसी। जिले के नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी रहे वरिष्ठ नेता शेख ज्वाउल हसन उर्फ जेड हसन ने क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों का व्यापक दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने नगर निगम के वार्ड संख्या 1, 2, 3 और 4 सहित सबौर प्रखंड के रजनदीपुर और बाबूपुर के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर पीड़ितों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं। दौरे के बाद राजद नेता जेड हसन ने कहा कि वे पिछले एक सप्ताह से नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित सबौर और नाथनगर प्रखंड की करीब 20 से अधिक पंचायतों का लगातार दौरा कर रहे हैं।

उन्होंने जमीनी हकीकत बयां करते हुए कहा कि स्थिति बेहद चिंताजनक है। कई स्थानों पर पीड़ितों को अब तक पॉलिथीन सीट तक नसीब नहीं हुई है। जिन इलाकों से पानी धीरे-धीरे निकल रहा है, वहां न तो स्वास्थ्य विभाग की टीमें पहुंची हैं और न ही संक्रमण से बचाव के लिए चूना या ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराया जा रहा है। जेड हसन ने राहत राशि के वितरण पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्राप्त जानकारी के अनुसार सबौर प्रखंड के लगभग 14 हजार और नाथनगर प्रखंड के 19 हजार परिवारों को ही जीआर की राशि उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने इन आंकड़ों को बेहद कम बताते हुए कहा कि जमीनी स्तर पर शिकायतों का अंबार है। जब आप गांवों के चौराहों और गलियों में जाएंगे, तो हर दूसरा व्यक्ति जीआर राशि न मिलने की शिकायत कर रहा है। उन्होंने मांग की कि जितने परिवारों को अब तक राशि



मिली है, कम से कम उतने ही और प्रभावित परिवारों को चिन्हित कर तुरंत सहायता राशि भेजने की जरूरत है। शहरी क्षेत्र के वार्ड नंबर 1, 2, 3 और 4 के भ्रमण का जिक्र करते हुए राजद नेता ने कहा कि स्थानीय बुनकर परिवारों की हालत बदतर है। बाढ़ प्रभावित बुनकरों ने उन्हें बताया कि वर्ष 2015 में उन्हें आखिरी बार जीआर की राशि मिली थी। तब से लेकर आज तक हर साल वे कमर भर पानी में डूबने को मजबूर हैं, लेकिन सरकार या प्रशासन की तरफ से कोई वित्तीय सहायता या जीआर की राशि नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि भागलपुर

जिले के लगभग 14 प्रखंड बाढ़ की चपेट में हैं, अतः सभी प्रभावित क्षेत्रों के पीड़ितों को समान रूप से सहायता मिले। जिन इलाकों से पानी निकल रहा है, वहां जलजनित बीमारियों और महामारी को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग की विशेष टीम, मोबाइल एंबुलेंस तथा बुनियादी दवाएं तुरंत तैनात की जाएं। जब तक प्रभावित क्षेत्रों में पूर्ण रूप से कीचड़ की सफाई और सैनिटाइजेशन का कार्य पूरा नहीं हो जाता, तब तक पीड़ितों के लिए सामुदायिक रसोई और राहत शिविरों का संचालन लगातार जारी रखा जाए।

बार-बार प्राकृतिक आपदाओं से घायल हो रहा भागलपुर, बुनियादी ढांचे की कमजोरी और मानवीय लापरवाही ने बढ़ाया संकट

भागलपुर,एजेंसी। बिहार का भागलपुर जिला इन दिनों एक बार फिर प्रकृति के भीषण प्रहार और प्रशासनिक विफलता के दोहरे संकट से जूझ रहा है। गंगा और उसकी सहायक नदियों के बढ़ते जलस्तर, तेज कटाव और तटबंधों पर बढ़ते दबाव ने पूरे जिले को सहमा दिया है। सितंबर महीने में जिले के कई इलाकों में तटबंध टूटने से बाढ़ की स्थिति भयावह हो गई है। लेकिन यह पहली बार नहीं है; बुनियादी ढांचे की मजबूती, तट सुरक्षा और आपदा से निपटने की तैयारियों पर उठ रहे गंभीर सवाल अब स्थानीय प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं।

भागलपुर की भौगोलिक स्थिति जहां इसका सबसे बड़ा गौरव है, वहीं इसकी सबसे बड़ी चुनौती भी बन चुकी है। कुछ महीने पहले, 3 मई की रात, जिले की जीवनरेखा कहे जाने वाले विक्रमशिला सेतु का करीब 33 मीटर का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त होकर गंगा नदी में समा गया था। इस हादसे के बाद नवगछिया और सीमांचल के इलाकों से संपर्क पूरी तरह टूट गया, जिससे दूध, सब्जी, केला और मछली जैसी रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति ठप हो गई। हालांकि सरकार ने तत्काल जांच और मरम्मत के निर्देश दिए थे, लेकिन बाढ़ के पानी के कारण काम में देरी हो रही है। मशीनों साइट पर पहुंचने के बावजूद काम शुरू न हो पाना आपदा के बीच दीर्घकालिक रणनीति के अभाव को दर्शाता है। हर साल आने वाली बाढ़ और कटाव को सिर्फ 'प्राकृतिक आपदा' कहकर पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, राधोपुर बांध के आसपास नदी के बढ़ते दबाव को लेकर तकनीकी विशेषज्ञों ने वर्षों पहले चेतावनी दी थी। इसके बावजूद समय रहते सुरक्षात्मक कदम नहीं उठाए गए। यह मानवीय लापरवाही और लचर तैयारियों का ही नतीजा



है कि आज दियारा क्षेत्र की एक बड़ी आबादी अपने घर, खेत और आजीविका बचाने के लिए दर-दर भटक रही है। आपदा के इस हाहाकार के बीच कहलगांव से आई एक तस्वीर ने पूरी व्यवस्था की संवेदनशीलता को तार-तार कर दिया है। यहां सार्वजनिक स्थल पर लगा राष्ट्रीय ध्वज क्षतिग्रस्त पाया गया, जो घंटों तक

जिम्मेदारों की नजरों से दूर पड़ा रहा। इस पर कुछ अधिकारियों की बचकानी दलीलों ने आग में घी का काम किया है।

स्थानीय राष्ट्रप्रेमियों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। नागरिकों का कहना है, 'राष्ट्रीय ध्वज कोई मामूली कपड़ा नहीं, बल्कि शहीदों की आन-

वर्चितों के चेहरे पर खिली मुस्कान: विशेष शिविर में बटे सहायक उपकरण, 26 को मिला पेंशन स्वीकृति पत्र



कटिहार। समाज कल्याण विभाग के तत्वावधान में आज प्रखंड कार्यालय कटिहार परिसर में जिला स्तरीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया। गरीब, वंचित और जरूरतमंद वर्ग के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से आयोजित इस शिविर में जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग और जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत दर्जनों लाभुकों को सीधे लाभ प्रदान किया गया।

शिविर में जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा 10 वृद्धजनों, 9 दिव्यांगजनों और 7 विधवा महिलाओं को विभिन्न पेंशन योजनाओं के स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। इसके साथ ही सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के 5 लाभुकों और मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत 1 लाभुक को लाभान्वित किया गया। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग की ओर से 18 दिव्यांगजनों को उनकी सुगमता के लिए आवश्यक सहायक उपकरण वितरित किए गए, जबकि 1 लाभुक को विशेष बैटरी चालित ट्राईसाइकिल सौंपी गई।

वहीं, समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित 'सक्षम' की 'उज्ज्वल दृष्टि योजना' के तहत 3 जरूरतमंद लाभुकों को चश्मा प्रदान किया गया।इस अवसर पर कटिहार सदर विधायक तारकिशोर प्रसाद और

जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने संयुक्त रूप से लाभुकों को स्वीकृति पत्र व उपकरण वितरित किए। शिविर में वरीय उप समाहर्ता श्री अभिषेक रंजन, कोशी क्षेत्रीय वृद्ध/विधवा/विकलांग समिति के सचिव शिव शंकर रमाणी, सामाजिक सुरक्षा कोषांग की सहायक निदेशक श्रीमती यशस्वी तथा बुनियाद केंद्र व सामाजिक सुरक्षा विभाग के कर्मी मौजूद रहे।

एक नजर

नेपाल के वित्त मंत्री वाग्ले और वित्त मंत्री सीतारमण के बीच दिल्ली में मुलाकात, पुनर्निर्माण पर चर्चा



काठमांडू, एप्रैसी। नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वाग्ले और भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बीच हुई मुलाकात में नेपाल में बाढ़ के बाद पुनर्निर्माण तथा नेपाल-भारत के बीच आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा हुई। भारत दौरे पर गएगी स्वर्णिम वाग्ले और उनकी समकक्ष निर्मला सीतारमण के बीच गुक्का शाम 5 बजे नई दिल्ली स्थित कार्यभवन परिसर में भारतीय वित्त मंत्रालय में मुलाकात हुई। बैठक में दोनों देशों के सरकारी प्रतिनिधिमंडलों के सदस्य भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान दोनों मंत्रियों ने विकास सहयोग और दोनों देशों के बीच लंबे समय से कायम आर्थिक साझेदारी से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। दौरे में शामिल प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बातचीत में बाढ़ के बाद पुनर्निर्माण, व्यापार, निवेश, ऊर्जा और कनेक्टिविटी समेत आपसी हित से जुड़े अन्य विषयों को शामिल किया गया। इसके अलावा नेपाल और भारत के बीच आर्थिक सहयोग को और मजबूत तथा व्यापक बनाने के अवसरों पर भी दोनों पक्षों के बीच चर्चा हुई।

होर्मुज़ जलडमरूमध्य में शिपिंग में रुकावट से दुनिया भर में उर्वरक की कमी

मार्को। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) ने कहा है कि होर्मुज़ जलडमरूमध्य में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध के कारण समुद्री यातायात बाधित होने के कारण विश्व भर में उर्वरक की कमी हो रही है और इसके फलस्वरूप ऊर्जा क्षेत्र सहित पूरे बाजार की स्थिति को चिंताजनक हो गया है। एफएओ के रूसी संघ स्थित संपर्क कार्यालय के निदेशक ओलेग कोबियाकोव ने रिया नोवोस्ती से बातचीत में कहा कि होर्मुज़ जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही में रुकावट के कारण दुनिया भर में उर्वरक की कमी हो रही है और बाजार की स्थिति खराब हो रही है, जिसमें ऊर्जा क्षेत्र भी शामिल है।

कोबियाकोव ने कहा, 'होर्मुज़ जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही में रुकावट के कारण दुनिया भर में उर्वरक की कमी हो रही है, जिससे उर्वरक बाजार में स्थिति बिगड़ रही है और ऊर्जा की कीमतें बढ़ रही हैं।' उन्होंने आगे कहा कि ईरान से जुड़ा संकट अब 'कुछ समय के लिए भड़के तनाव' से बदलकर एक लंबी चलने वाली बड़ी समस्या बन गया है। 28 फरवरी को, अमेरिका और इजराइल ने ईरान में ठिकानों पर हमले शुरू किए, जिसके जवाब में ईरान की तरफ से भी हमले किए गए। जून के मध्य में, तेहरान और वाशिंगटन ने लड़ाई रोकने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, हालांकि बाद में उन्होंने फिर से एक-दूसरे पर हमले किए। फिलहाल, यह संघर्ष सुलझ नहीं है। संघर्ष बढ़ने के कारण होर्मुज़ जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही लगभग ठप हो गई है। यह तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) के वैश्विक बाजार के लिए एक अहम सप्लाई स्ट्र है। नतीजतन, दुनिया भर के ज्यादातर देशों में ईंधन की कीमतें बढ़ गई हैं।

**संयुक्त राष्ट्र महासचिव पद की उम्मीदवार,
रूस-यूक्रेन के बीच सीधी बातचीत की पक्षधर**

संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र महासचिव पद की उम्मीदवार कैरॉलिन रोड्रिग्स-बिर्केट ने कहा कि अगर वह चुनी जाती हैं, तो शांति की दिशा में काम करने के लिए रूस और यूक्रेन के बीच सीधी बातचीत की पक्षधर हैं। रोड्रिग्स-बिर्केट ने रियानोवोस्की को बताया, 'जैसा कि मैंने कई मौकों पर कहा है, मैं अधिकारियों से बात करने में नहीं हिचकिचाऊंगी-चाहे वे यूक्रेन में हों, रूस में हों या किसी अन्य संघर्ष में शामिल हों—यैसा मकसद हमेशा शांति की दिशा में काम करना होगा। उनकी राय है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव को एक निष्पक्ष मध्यस्थ के तौर पर काम करना चाहिए और न केवल संघर्ष में शामिल सभी पक्षों से बात करनी चाहिए, बल्कि इसे होने से रोकने की कोशिश भी करनी चाहिए। फिलहाल, संयुक्तराष्ट्रके इस शीर्ष पद के लिए आठ उम्मीदवार हैं। इनमें इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रॉसी, युगांडा के पूर्व विदेश मंत्री ओलारा ओदुनुओ और सेनेगल के पूर्व राष्ट्रपति मैकौ साल शांतिम हैं। महिला उम्मीदवारों में चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बालेगोटे, इक्वाडोर की पूर्व विदेश मंत्री मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा, इक्वाडोर की राजनयिक इवोन ए-बाकी, संयुक्तराष्ट्रकार्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की महासचिव रेबेका ग्रीनस्पैन, गुयाना की पूर्व विदेश मंत्री कैरोलिन रोड्रिग्स-बिर्केट और बच्चों और सशस्त्र संघर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव की विशेष प्रतिनिधि वर्जीनिया गेम्बा शामिल हैं। मौजूदा संयुक्तराष्ट्रमुख एंटोनियो गुटेरेस का दूसरा और आखिरी कार्यकाल 31 दिसंबर को खत्म होगा।

बलोचिस्तान : तुर्बत में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला, कई जवान हताहत

तुर्बत। पाकिस्तान के बलोचिस्तान प्रांत के केच जिले के मुख्यालय तुर्बत में बुधवार को पाकिस्तानी फोर्स के एक काफिले पर हमले की खबर सामने आई है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार, डबोक मैनो क्रॉस के पास हथियारबंद लोगों ने काफिले को निशाना बनाया। बलोचिस्तान की ऑनलाइन समाचार नेटवर्क 'द बलोचिस्तान पोस्ट' ने बताया कि शुरुआती स्थानीय रिपोर्टों में दावा किया गया है कि हमले में कई जवान मारे गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक, घटना के बाद मौके पर चार शव देखे गए और इलाके में सुरक्षा बलों की अतिरिक्त टुकड़ियां भेजी गईं। सूत्रों ने हमले में मारे गए फ्रंटियर कॉर्पस (एफसी) के दो जवानों की पहचान खाईल महमूद और रमजान जट्ट के रूप में की है। बताया गया है कि दोनों पंजाब के मियांवाली जिले के रहने वाले थे। हालांकि, रिपोर्ट सामने आने तक घटना को लेकर पाकिस्तानी अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है और न ही किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी ली है।

लाल सागर में तनाव के बीच मस्कट में अमेरिका-हूती के बीच हुई गुप्त बैठक



के अनुरोधों को स्वीकार नहीं किया है।

सूत्र ने बताया कि अमेरिका की ओर से बैठक में अमेरिकी दूतावास के राजनयिक शामिल हुए। लोकेशन अमेरिकी राजदूत इसमें मौजूद नहीं थे। बैठक के दौरान हूती प्रतिनिधियों ने कथित तौर पर कहा कि वे अमेरिका के साथ मई 2025 में हुए युद्धनियम को जारी रखना चाहते हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि हाल में फिर शुरू हुई अरबी कार्रवाई केवल सख्ती जहाजों को गिराना बना रही है। साथ ही हूतियों ने बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य से अखन जहाजों की आवाजाही की स्वतंत्रता बनाए रखने का आश्वासन भी दिया। अमेरिकी विदेश विभाग ने बैठक की खबरों पर सीधे टिप्पणी करने से इनकार किया। विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि

मध्य पूर्व में अमेरिका के प्रमुख हितों में लाल सागर और क्षेत्र में आवाजाही की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना तथा आतंकवाद के प्रसार को रोकना शामिल है। प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिकी यमन को लेकर अपने क्षेत्रीय सहयोगियों और साझेदारों के साथ नियमित संपर्क में है। उन्होंने कहा कि अमेरिका हूतियों और अन्य आतंकवादी समूहों के खिलाफ सहा आतंकवाद-रोधी लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। बैठक के एक दिन बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पत्रकारों से कहा कि अमेरिका हूतियों के साथ बातचीत कर रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सीधे तौर पर हूतियों से बातचीत में शामिल रहा है और प्रशासन को मानना है कि वह स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश

कर रहा है। इसी बीच, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ओमान के विदेश मंत्री सैयद बद्र अल-बुसैदी से क्षेत्रीय तनाव कम करके के प्रयासों को लुप्तवाचनीयता की। लाल सागर संकट के बीच यमन में हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब के बीच तनाव हाल के दिनों में बढ़ा है। हूतियों की ओर से सऊदी अरब पर ड्रोन और मिसाइल हमलों की खबरें सामने आई हैं। इनमें मक्का की दिशा में ड्रोन हमलों और सऊदी अरब के अन्य शहरों को निशाना बनाने वाले मिसाइल हमले भी शामिल हैं। सऊदी अरब ने यमन में हूती फ़िक्कानों के खिलाफ हमलाई हूतों तेज किए हैं। हालांकि, सऊदी समर्थित यमनी बलों के अब तक जमीन पर हूतियों के खिलाफ निर्णायक बढ़त हासिल नहीं हुई है।

ट्रंप ने कनाडा की 'एसोसिएट मेंबरशिप' को लेकर यूरोपीय संघ को दी चेतावनी

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ (ईयू) को चेतावनी दी है कि यदि कनाडा को ब्लॉक का 'सहयोगी सदस्य' बनाने की योजना आगे बढ़ती है तो अमेरिका यूरोप पर भारी टैरिफ लगा सकता है और कुछ क्षेत्रों में व्यापार रोकने पर भी विचार कर सकता है। ट्रंप ने ईयू के इस प्रस्ताव को संभावित रूप से 'शत्रुतापूर्ण कदम' बताया है। ट्रंप ने कहा कि यदि ईयू की मंशा अच्छी हुई तो स्थिति अलग होगी, लेकिन खराब इशारे होने पर यूरोप को भारी शुल्क का सामना करना पड़ सकता है।

यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने बुधवार को कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की मौजूदगी में कनाडा को ईयू का पहला 'सहयोगी सदस्य' बनाने का प्रस्ताव रखा। यह पहल ईयू और कनाडा के संबंधों को मौजूदा व्यापार समझौते से आगे बढ़ाने की योजना का हिस्सा है। वॉन डेर लेयेन ने रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), साइबर सुरक्षा और आर्थिक सहित रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की बात कही है। कनाडा पहले से ही ईयू के साथ व्यापक आर्थिक एवं व्यापार सेवाओं में सहयोग को लेकर भी चर्चा हुई है। कनाडा और अमेरिका के बीच जारी व्यापारिक तनाव के बीच ओटावा यूरोप के साथ अपने आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को विस्तार देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसे में टूट की चेतावनी से अमेरिका और ईयू के बीच व्यापार संबंधों को लेकर तनाव बढ़ने की संभावना है। कनाडाई प्रधानमंत्री कार्नी गुस्वर से यूरोपीय संसद को संबोधित करेंगे। इसके बाद कनाडा और ईयू के बीच प्रस्तावित नए संबंधों की रूपरेखा को लेकर आगे की बातचीत होने की उम्मीद है।

समझौते (सीडीए) के तहत व्यापारिक संबंध रखता है। हालांकि, प्रस्तावित 'सहयोगी संरचना' की विस्तृत शर्तें अभी तय नहीं हुई हैं। यह भी स्पष्ट नहीं है कि नई व्यवस्था के तहत कनाडा को ईयू के एकल बाजार तक कितनी पहुँच मिलेगी और उसे किन यूरोपीय नियमों को अपनाना होगा। कनाडाई सरकार ने ईयू के साथ संबंधों को और मजबूत करने तथा रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की इच्छा जताई है।

कानी और वॉन डेर लेयेन के बीच महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा उद्योग, ऊर्जा, एआई, अंतरिक्ष और वित्तीय सेवाओं में सहयोग को लेकर भी चर्चा हुई है। कनाडा और अमेरिका के बीच जारी व्यापारिक तनाव के बीच ओटावा यूरोप के साथ अपने आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को विस्तार देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसे में ट्रंप की चेतावनी से अमेरिका और ईयू के बीच व्यापार संबंधों को लेकर तनाव बढ़ने की संभावना है। कनाडाई प्रधानमंत्री कानी गुरुवार को यूरोपीय संसद को संबोधित करेंगे। इसके बाद कनाडा और ईयू के बीच प्रस्तावित नए संबंधों की रूपरेखा को लेकर आगे की बातचीत होने की उम्मीद है।

क्षेत्रीय तनाव के बीच ईरानी राष्ट्रपति ने कहा- पड़ोसियों के साथ विवाद सुलझाने को तैयार

तेहरान, एजेंसी। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशीकियान ने कहा है कि उनका देश अपने पड़ोसी देशों के साथ बातचीत, आपसी समझ और सम्मान के जरिए मतभेदों को सुलझाने के लिए तैयार है। उन्होंने क्षेत्रीय देशों से सहयोग बढ़ाने और अस्थिरता के कारणों को कम करने का आह्वान किया। ईरान सरकार की अंतरराष्ट्रीय समाचार नेटवर्क प्रेस टीवी के अनुसार, इराक के पैट्रियटिक यूनियन ऑफ कुर्दिस्तान (पीयूके) के प्रमुख बाफल तलबानी के साथ बैकबैंक में राष्ट्रपति मसूद पेजेशीकियान ने ईरान और इराकी कुर्दिस्तान के लोगों के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों को महत्वपूर्ण बताया।

पेजेशकियन ने आरोप लगाया कि अमेरिका और इजराइल क्षेत्रीय देशों को कमजोर करने और उनके संसाधनों का फायदा उठाने के लिए विभाजन और संघर्ष को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयासों का मुकाबला करने के लिए क्षेत्र के देशों को आपसी सहयोग और संवाद बढ़ाना चाहिए। ईरानी राष्ट्रपति ने कहा कि यदि किसी समूह की जायज मांगें हैं, तो ईरान बातचीत और आपसी सम्मान के दायरे में उन मुद्दों को सुलझाने के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने पड़ोसी देशों से भी अनुचित व्यवहार और अत्यधिक मांगों से बचने की अपील की। उन्होंने मुस्लिम देशों के बीच साझा धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान सहयोग, बातचीत, निष्पक्षता और न्याय के जरिए किया जा सकता है। बैठक के दौरान पेजेशकियन ने



ईरान और इराकी कुर्दिस्तान क्षेत्र आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को करने पर भी जोर दिया। वहीं, बाफेवल ने ईरान को इराकी कुर्दिस्तान क्षेत्र का मित्र बताते हुए दोनों पक्षों के बीच बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। तलबानी सुर्क्षा को महत्वपूर्ण बताते हुए कुर्दिस्तान क्षेत्र से लगी ईरान की सीमा में मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं कहा कि ईरान और इराक के बीच हुए समझौते के तहत सीमावर्ती इलाकों में सशस्त्र-विरोधी समूहों से निपटने और स्थिरता बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा तलबानी के साथ एक आर्थिक टीम

पहुंची, जिसका उद्देश्य व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करना था। तलबानी की ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहमेन रेजाई के साथ भी बैठक हुई। रेजाई ने सीमा सुरक्षा और अतंकवादी समूहों से निपटने को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने इराकी कुर्दिस्तान क्षेत्र में इजराइल की गतिविधियों को लेकर भी चेतावनी दी। अमेरिका के साथ संबंधों पर रेजाई ने कहा कि ईरान को अमेरिका पर भरोसा नहीं है और विश्वास बहाल करने के लिए वॉशिंगटन को व्यावहारिक कदम उठाने होंगे वहीं तलबानी ने ईरान के साथ आर्थिक, सुरक्षा और कूटनीतिक सहयोग बढ़ाने का समर्थन किया।

हिमालयी पर्वत शिखर लांगटांग लिरुंग पर हिमनदी का हिस्सा अभी भी मौजूद, खिसकना बाकी



अनुसार जिस हिस्से से हिमनदी और चट्टानें खिसककर विनाशकारी बाढ़ की वजह बनी थीं, वहां अभी भी हिमनदी और पहाड़ का कुछ हिस्सा अस्थिर अवस्था में मौजूद है। इसके अलावा उसी क्षेत्र में बर्फ से ढकी रहने वाली एक झील अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी है। जल विज्ञान तथा जलस्रोत अनुसंधान केंद्र के उप कार्यकारी निदेशक विक्रम श्रेष्ठ के अनुसार, चीन से प्राप्त हालिया सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि हिमनदी का कुछ हिस्सा अभी भी लटका हुआ है और भाविष्य में खिसक सकता है। हालांकि, यह हिस्सा कितना बड़ा है और कब बखसि देगा, इसका अभी निश्चित आकलन नहीं किया जा सका है। इसलिए केवल इन संकेतों के आधार पर तत्काल एक और बड़े हिमखलन की भाविष्यवाणी नहीं की जा सकती। चीनी एकडेमी ऑफ साइंसेज के निम्बती पठार अनुसंधान संस्थान के अध्ययन के अनुसार, 26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में खिसका बर्फांगणों का हिस्सा करीब 980 मीटर चौड़ा और 10 मीटर लंबा था। इसका क्षेत्रफल 0.76 वर्ग किलोमीटर और मध्य गहनमीटर से अधिक आंकी गई है। और बढ़ते समय इस विशाल क्षेत्र में अन्य चट्टानों और सामग्री को साथ बहाया। विशेषज्ञों के अनुसार सैटेलाइट विश्लेषण में संकेतित 12 से 24 अगस्त के बीच उस क्षेत्र में असामान्य हलचल बढ़ गई। चट्टानी हिस्सा प्रतिदिन करीब 10 सेंटीमीटर तक खिसक रहा था। हालांकि विश्लेषण घटना के बाद किया गया है। इससे यह नहीं कहा जा सकता है इस समय हिमखलन की सीटी बज रही है। सैटेलाइट तस्वीरों में पहले बर्फ से ढकी रहने वाली

मगस्त को अब स्पष्ट दिखाई दे रही है।

और चट्टान इसका क्षेत्रफल करीब 0.15 किलोमीटर, यानी लगभग 27 अंतराष्ट्रिय फुटबॉल मैदानों के बराबर है। अभी तक की गहराई और उसमें मौजूद पानी की मात्रा के बारे में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है। विशेषज्ञों के मुताबिक, इस झील से पानी निकालकर रिसक यदि पहाड़ की दरारों में पहुंचे तो इससे चट्टानी हिस्से की स्थिरता प्रभावित हो सकती है। इसलिए झील और पहाड़ के क्षेत्र की लगातार सेंटेलाइट निगरानी की जा रही है। पिपलहाल वैज्ञानिकों का मानना ​​है कि पर्वत चट्टान लांगटर्म लिक्विड है। कुछ बर्फ और झिल्ली हिस्सा अभी भी अस्थिर है, लेकिन उसके खिसकने से पहले समय, आकार और संभावित प्रभावों को निश्चित अनुमान अभी उपलब्ध नहीं है। इसी वजह से क्षेत्र की नियमित निगरानी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

आईईए की परमाणु निरस्त्रीकरण की मांग को उत्तर कोरिया ने दुकराया

सियोल। उत्तर कोरियाई नेता किम जो-अ-उन की जहन और वरिष्ठ अधिकारी किम यो-जोंग ने अंतरराष्ट्रीय परमाणु निस्स्त्रुकीकरण की मांग को खारिज करते हुए कहा है कि उत्तर कोरिया का परमाणु हथियार संपन्न देश का दर्जा स्थायी है। दक्षिण कोरिया की सरकारों समाचार एजेंसी योनहाप के मुताबिक, किम यो-जोंग ने गुस्सवार को जारी बयान में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) की मांगों को खारिज किया। उनका बयान ऑस्ट्रिया के वियना में चल रहे आईएईए के 70वें जनरल कॉन्फ्रेंस सत्र के दौरान आया है। आईएईए सम्मेलन में उत्तर कोरिया की बढ़ती परमाणु क्षमताओं पर चिंता जताई गई है। एजेंसी ने प्योंगयांग से परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) के तहत अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को पूर्ण तरह, स्थापना योग्य और स्थायी रूप से खत्म करने की मांग की है।

सम्मेलन से पहले जारी आईएसईए की सेफगार्ड्स रिपोर्ट में उत्तर कोरिया की भूमिनिम्नमूलक संवर्धन क्षमता में बढ़ोतरी और प्रमुख परमाणु-सम्बन्धित सुविधाओं के विस्तार का भी उल्लेख किया गया था। किम यो-जोंग ने इन मामलों को खारिज करते हुए कहा कि आईएसईए और पश्चिमी देशों का बैठकों तथा परमाणु-परीक्षण निस्स्वीकारण की मांगों का उत्तर कोरिया की नीति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि देश अपने राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाता रहेगा। किम यो-जोंग ने कहा कि उत्तर कोरिया का परमाणु-परीक्षण हथियार संपन्नता का दर्जा अटल है और इसे किसी बाहरी दबाव से बदला नहीं जा सकता।



IAEA
International Atomic Energy Agency

उन्होंने यह भी कहा कि देश की परमाणु क्षमता में हुए बदलावों को कोई पीछे नहीं ले जा सकता। उनको यह दिपण्णी ऐसे समय और जगह अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरियाई नेता किम जोङ-उन के साथ संभावित शिखर वार्ता में रूचि दिखाई है। दक्षिण कोरिया के एकीकरण मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि मंत्रालय किम यों-जोंग के बयान पर नजर रख रहा है। अधिकारी के अनुसार, बयान को संभावित अमेरिका-उत्तर कोरिया शिखर वार्ता में परमाणु निस्स्त्रीकरण के मुद्दे पर प्योंगयांग की स्थिति स्पष्ट करने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। इस बीच, उत्तर कोरिया के रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच बड़े पैमाने पर विनाशकारी हथियारों (डब्ल्यूएमडी) से निपटने को लेकर हुई हालिया बैठक की आलोचना की। पिछले सप्ताह हुई संयुक्त डब्ल्यूएमडी काउंटरमेज़र्स कमेटी की वार्षिक बैठक में सियोल और वॉशिंगटन ने उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को दखाते हुए डब्ल्यूएमडी से संबंधित जानकारी साझा करने की प्रक्रिया को मजबूत करने पर सहमति जताई थी।

एक नजर

**पुतिन ने मोदी को जन्मदिन की बधाई दी,
भारत-रूस रणनीतिक साझेदारी मजबूत
करने में योगदान की सराहना की**

नई दिल्ली, एप्रैल ३१। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 76वें जन्मदिन पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और भारत में अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो काउसीनो ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दीं। तीनों संदेशों में भारत के साथ अपने-अपने देशों के संबंधों को मजबूत करने में मोदी को भूमिका का उल्लेख किया गया। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी पुरानी मुलाकात की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर साझा करते हुए अपने संदेशों में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को अपने देशवासियों का गहरा सम्मान और वैश्विक मंच पर व्यापक प्रतिष्ठा प्राप्त है। भारत और रूस के बीच विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने में मोदी के व्यक्तिगत योगदान को कम करके नहीं आंका जा सकेगा। पुतिन ने पिछले सप्ताह नई दिल्ली में अपनी यात्रा के दौरान मिले गम्भीर जोश और स्वैग और आतिथ्य के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत सार्थक, स्पष्ट और उत्पादक रही।

रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि दोना देशों का हित में द्विपक्षीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर रचनात्मक सहयोग आगे भी जारी रहेगा। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी पुरानी मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए 'एक्स' पर जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत को विश्व शक्ति में बदल दिया है। नेतान्याहू ने भारत और इसराइल के बीच साझेदारी को अभूतपूर्व बताते हुए कहा कि दोनों देशों की मित्रता पहले से अधिक मजबूत है और इसे आगे नई ऊँचाइयों तक ले जाया जाएगा। भारत में अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो काउसीनी ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने मोदी के साथ मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए अर्जेंटीना की सरकार और जनता की ओर से शुभकामनाएं प्रेषित कीं। प्रधानमंत्री मोदी को उनके जन्मदिन पर विश्वभर देशों के नेताओं और राजनयिक प्रतिनिधियों की ओर से शुभकामनाएं मिली हैं।

महेंद्रगढ़ में मुख्यमंत्री ने 135 करोड़ की परियोजनाओं का किया शुभारंभ

नारनौल, एजेंसी। मुख्यमंत्री नयब सिंह सैनी गुरवार को महेंद्रगढ़ के खेल स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय विश्वकर्म महर्जती समारोह में पहुंचे। इससे पहले उन्होंने कैची को कर पुर महाराजा शूरसैनी की प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ाने की घोषणा की। सरकार के अनुसार अब एक लाख 80 हजार रुपये तक वार्षिक पारिवारिक आय वाली पात्र महिलाओं को भी योजना में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले एक लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों की महिलाएं योजना का लाभ ले रही थीं। इससे करीब 10 लाख महिलाएं लाभान्वित हो रही थीं। आय सीमा बढ़ाए जाने के बाद करीब 17 लाख नए पात्र महिलाओं को योजना से जोड़ने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को योजना की पहली पांच लाभार्थी महिलाओं के साथ फोटो भी खिंचवाई। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल से महेंद्रगढ़ क्षेत्र के लिए 135 करोड़ 82 लाख रुपये की वित्तिन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें दुलित अहीर से राजस्थान के सोहली बाँईर तक सड़क तथा सोहली बाँइत में 15 करोड़ रुपये की लागत से वाटर बाँडी का निर्माण शामिल है।

इसके अलावा अन्य गावों में भी 15 करोड़ रुपये की लागत से चार घण्टे बाँट दिया जिससे कर्नाट की घोषणा की गई। उन्होंने जाँजिङ्ग धर्मशाला मेंहंदिकट में छात्रावास निर्माण के लिए 31 लाख रुपये देने की घोषणा की। नगर पालिका चेयरमैन शूर सैनी चौक के लिए भी 21 लाख रुपये की गाँव देने की बात कही। मुख्यमंत्री ने विश्वकर्मा समाज और श्रमिकों के योगदान का उल्लेख करते हुए विकास कार्यों को गति देने की बात कही। राज्य सरकार के अनुसार लाडो लक्ष्मी योजना के नए पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण 17 सितंबर से शुरू किया जाना है और पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2100 रुपये की सहायता मिलेगी। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अर्चना गुप्ता, स्वास्थ्य मंत्री आरती राव, सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा, सांघर्व चौधरी धर्मवीर सिंह, विधायक ओमप्रकाश यादव, विधायक कंवर सिंह यादव और पूर्व विधायक डॉ. अभय सिंह सहित अनेक लोग मौजूद रहे।

निजाम के शासनकाल में तेलंगाना सामंती शोषण और उत्पीड़न से प्रभावित था : रेवंत रेड्डी

हैदराबाद, एर्जेसी । तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेड्डी ने कहा कि निज़ाम के शासनकाल के दौरान ग्रामीण तेलंगाना सामंती शोषण, बंधुआ मजदूरी और उत्पीड़न से प्रभावित था । तेलंगाना सरकार ने गुरुवार को नामपल्लिवी पब्लिक गाइडेंस में अपना 'प्रजा पालना दिनोत्सव' कार्यक्रम किया । इस मौके पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और पेरेंड की सलामी ली ।

कार्यक्रम को संबंधित करते हुए मुख्यमंत्री रेड्डी ने निजाम शासन के इसमें हैदराबाद के इतिहास और भारतीय संघ में इसके विलय का निजाम बनने वाली घटनाओं को याद किया। उन्होंने कहा कि निजाम के शासनकाल के दौरान हैदराबाद में उद्योग, कृषि, शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की थी और वैश्विक प्रभाव बनाई थी। साथ ही, उन्होंने कहा कि निजामों तेलंगाना सामंती शोषण, बंधुआ मजदूरी और उत्पीड़न से प्रभावित था। उन्होंने कहा कि निजाम शासन के सशस्त्र समर्थकों, रज्जाकारों द्वारा किए गए अत्याचारों ने अंतिम चरण में लोगों को और संकट और संघर्ष में धकेल दिया। उन्होंने उन प्रवासियों और हैदराबाद स्टेट कांग्रेस की आंध्र आंदोलनों में भूमिका का भी जिक्र किया, जिनका उद्देश्य हैदराबाद को भारत का अभिन्न अंग बनाना था, जबकि कम्युनिस्टों ने रज्जाकारों के अत्याचारों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष आयोजित किया था। विलय को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पहले

**प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर काशी से वडनगर
के लिए रवाना हुए 500 बाइकर्स, प्रत्येक
पड़ाव पर होंगी विविध सेवा गतिविधियां**

वाराणसी, एजेंसी । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 76वें जन्मदिन और सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित 'सेवा संकल्प बाइक यात्रा' के तहत पुरवारा को काशी से 500 बाइकर्स वडनगर के लिए रवाना हुए । रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में 250 बाइक पर सवार युवाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया । काशी से वडनगर के लिए 10 अलग-अलग मार्गों पर यात्रा शुरू हुई । कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू, केन्द्रीय मंत्री चिराग पासवान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, यात्रा संयोजक एवं खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा, आंध्र प्रदेश के सांसद लवु श्रीकृष्ण और सतीश बाबू तथा भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री एवं उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी जगदीश भाई पटेल सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे ।

17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलने वाली 'वाराणसी से वडनगर सेवा यात्रा' में देशभर के 500 से अधिक युवा हिस्से लगे। यात्रा 20 मार्गों से होकर 10 राज्यों के 193 जिलों, 773 तहसीलों और 1,159 गांवों से गुजरेगी। प्रत्येक पड़ाव पर करीब 25 प्रकार की सेवा गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इसी तरह वडनगर से वाराणसी की और भी बाक़स यात्रा करेंगे। भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं



उप-प्रधानमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने हैदराबाद के लोगों की आकांक्षाओं को समझा और 1948 में 'ऑपरेशन पोलो' के नाम से जानी जाने वाली सैन्य कार्रवाई शुरू की। उन्होंने राज्य की विकास योजनाओं पर भी बात की और कहा कि सरकार दिसंबर में 'तेलंगाना ग्लोबल समिट-2026' के दौरान 'भारत प्यूर चरिटी' का मास्टर प्लान पेश करेगी। उन्होंने बताया कि प्यूर चरिटी में विशिष्ट क्षेत्र होंगे, जिनमें यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी, लाइफ साइंसेस हेब, ईवी पार्क, एआई

सिटी, हेल्थ सिटी और एजुकेशन सिटी शामिल हैं।
उल्लेखनीय है कि 17 सितंबर, 1948 को भारतीय
संघ में हैदराबाद रियासत के विलय को अलग
अलग तरीके से याद किया जाता है। भाजपा ने
दिन को निजाम शासन के अंत और रज़ाकार
प्रतिरोध से जोड़ते हुए ' हैदराबाद मुक्ति दिवस
कहती है। कांग्रेस इसे राजशाही से लोकतंत्र में
परिवर्तन का प्रतीक मानते हुए 'प्रजा शासन
दिवस' कहती है। वहीं जोआरएस ने सेता में रहते
हुए इसे 'राष्ट्रीय एकता दिवस' कहा था।

जंतर-मंतर पर धरने की अनुमति न मिलना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश: एआईएमपीएलबी



नई दिल्ली, एन॰सी॰ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने जंतर-मंतर पर आज प्रस्तावित धरना-प्रदर्शन की अंतिम समय में दिल्ली पुलिस से अनुमति न मिलने पर गर्हर्षितता व्यक्त करते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। बोर्ड ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों के मौलिक संवैधानिक अधिकार हैं और प्रशासनिक निर्णयों के माध्यम से इन पर अंकुश नहीं लगाया जाना चाहिए।

प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में संवाददाता सम्मेलन में बोर्ड के उपाध्यक्ष सैयद सआदतुल्लाह हुसैन मौलाना ओबैदुल्लाह खान आजमि, मौलाना असदुल्लाह इमाम महदी खान, महासचिव मौलाना मोहम्मद फजलुलहीम मुजहिदी, सचिव मौलाना मोहम्मद उमरैन महफूज़ रहमानी, प्रवक्ता डॉ. कासिम रसूल इलियास ने बताया कि बोर्ड प्रवक्ता और 'संविधान बचाओ, देश बचाओ' अभियान के संयोजक डॉ. सैयद कासिम रसूल इलियास पिछले दस दिनों के दौरान तीन बार पार्लियामेंट स्ट्रीट

पुलिस स्टेशन गए और थाना प्रभारी (एसएचओ) तथा पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) को आश्वासन दिया कि धरने में शामिल होने वाले लोगों की संख्या निर्धारित सीमा के भीतर रहेगी। इसके बावजूद पुलिस ने निषेधित कार्यक्रम से ठीक एक दिन पहले यह कहकर धरने की अनुमति वापस ले ली गई कि पुलिस का बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की आशंका है।

बोर्ड ने इस निर्णय को एकतरफा और अनुचित बताया तथा कहा कि वह पहले भी निर्धारित समय के भीतर और शर्तों का पालन करते हुए जंतर-मंतर नियमों का पूर्ण प्रदर्शन आयोजित कर चुके हैं। बोर्ड स्पष्ट किया कि प्रस्तावित धरना उद्यम राष्ट्रव्यापी संविधान बचाओ, देश बचाओ अभियान का पहला चरण था। इस अभियान का उद्देश्य समाज के वंचित और हाशिए पर पड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यक विशेषकर मुसलमानों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, भीड़ द्वारा पीटकर हत्या व घटनाओं, जीवन, प्रतिभा, गरिमा और सम्मान पर हमलों, मस्जिदों, मंदिरों और मुस्लिम बस्तियों

संभालन की कामना कर रहे हैं। बंदरगाह नगरी पारादीप में भी विश्वकर्मों पूजा को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। विभिन्न श्रमिक संगठनों के अलावा ट्राॅल्ल ओनर्स एसोसिएशन और ट्रक ओनर्स एसोसिएशन की ओर से बड़े पैमाने पर पूजा का आयोजन किया गया है। पारादीप में करीब 15 बड़े और छोटे पूजा मंडप बनाए गए हैं, जहां श्रमिक अनुष्ठान आयोजित किए जा रहे हैं। शाम को विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। विश्वकर्मों पूजा विशेष रूप से औद्योगिक श्रमिकों, मैकेनिकों, इंजीनियरों, कारीगरों, परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोगों और विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस अवसर पर लोग अपने कार्य और आजीविका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले औजारों एवं मशीनों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने लगाए 76 शिविर, 58 दिव्यांगजन और बुजुर्गों को दिए गए सहायक उपकरण

नई दिल्ली, एजेंसी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने अल्पकोट के सहयोग से गुरुवार को 21 राज्यों के 76 स्थानों पर एक सार्वजनिक शिथिर आयोजित किए। इन शिथिरों में 58 हजार से ज्यादा दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को करीब 68 करोड़ रुपये के सहायक उपकरण मुफ्त दिए गए। ये उपकरण लोगों को जरूरत के हिसाब से बांटे गए। इनसे उन्हें चलने-फिरने, रोजमर्रा के काम करने और आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी।

लालकिला स्थित लव कुश रामलीला मैदान में गुरुवार को शिविर का उद्घाटन करते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि सहायक उपकरण सिर्फ मदद करने वाली चीजें नहीं हैं, बल्कि इनसे दिव्यांगजन और बुजुर्गों को आत्मविश्वास, सम्मान और स्वतंत्र रूप से जीवन जीने में मदद मिलती है। सरकार की कोशिश है कि जरूरतमंद लोगों तक सहायता योजनाओं और सहायता का लाभ सीधे पहुंचे। मंत्री ने बताया कि देशभर में 109 प्रधानमंत्री दिव्यांगता-व्योशी केंद्र चल रहे हैं। इन केंद्रों के जरिए दिव्यांगजनों और बुजुर्गों को जरूरी सेवाएं उनके नजदीक उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। देश में 28 संसित विंडो क्रॉस-डिसएबिलिटी अलॉय इंटरवेंशन सेंटर शुरू



किए गए हैं। इन केंद्रों के जरिए दिव्यांग बच्चों और उनके परिवारों को जरूरी सहायता और पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा दिव्यांग खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। ग्यालियर में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए खेल केंद्र भी बनाया गया है। नई दिल्ली में आयोजित शिबिर में 463 लोगों को 2,450 सहायक उपकरण दिए गए। इनमें 446

बुजुर्ग और 17 दिव्यांगजन शामिल थे। इन उपकरणों की कुल कीमत करीब 34.96 लाख रुपये थी। लाभार्थियों को उनकी जरूरत के अनुसार मोटर वाली कार, ट्राइसाइकिल, ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी, छड़ी, वॉकर, सुनने की मशीन, कम्पोड व्हीलचेयर, कम्पोड चेयर, घुटने के ब्रेस और अन्य उपकरण दिए गए। इन शिविरों से पहले लाभार्थियों की जरूरत को जांच की गई थी। इसके बाद उनकी जरूरत

के अनुसार उपकरण दिए गए।

मंत्री ने कहा कि दिव्यांगजनों और बुजुर्गों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों, जिला प्रशासन, सामाजिक संगठनों, और अन्य संस्थाओं को भी मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, स्कूलों, सार्वजनिक स्थानों और परिवहन व्यवस्था को दिव्यांगजनों के लिए आसान और सुविधाजनक बनाने पर भी जोर दिया। अल्मिको के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक प्रवीण कुमार ने कहा कि संस्था अच्छी गुणवत्ता वाले सहायक उपकरण उपलब्ध कराने और डिजिटल तकनीक के जरिए सेवाओं को आसान बनाने पर काम कर रही है। जरूरतमंद दिव्यांगजनों और बुजुर्गों तक सही उपकरण समय पर पहुंचाना अल्मिको की प्राथमिकता है। इन सामाजिक अधिकारिता शिविरों का उद्देश्य दिव्यांगजनों और बुजुर्गों को जरूरी सहायता उपलब्ध करारकर उन्हें सम्मान के साथ और अधिक आत्मनिर्भर जीवन जीने में मदद कराना है। कार्यक्रम में चांदनी चौक के सांसद प्रवीण खंडेलवाल, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना, मंत्रालय की अपर सचिव मनमोती नंदा और अल्मिको के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक प्रवीण कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।

दादाबाद के हस्तशिल्प, मेटल

टैवियर और स्थानीय दस्तकारी कर्मियों द्वारा राष्ट्रीय पटल पर सीधे नए बाजारों में खरीदार दिलाने के लिए खाकियाँ बिक्री हो चुकी हैं। ग्रेटर नोएडा स्थित एनडीओपी सेंटर एंड मार्ट में 25 से अधिक सिंठंबर तक आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में 'उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो' का शुभारम्भ हुआ। मुंबाईबाद जनपद से कुल 78 व्यापारी, नए व उद्यमि निर्माताओं सहित हेल्ला एवं युवा स्थापित निर्माताओं की डीओपी दस्तकार अपनी मजबूत प्रतिष्ठा दर्ज कराएंगे।

[illegible]

को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। ट्रेड
शो के ले-आउट के अनुसार, इस बार
सबसे क्रांतिकारी बदलाव नए
निर्यातकों के रूप में सामने आया है।
पहली बार सीधे विदेशी खरीदारों के
सामने अपने उत्पादों की प्रदर्शनी
लगाने जा रहे नए कारोबारियों के लिए
तय हॉल नंबर 14 (न्यू एक्सपोर्टर्स)
में अकेले मुरादाबाद के 42 नए
निर्यातकों ने अपने स्टॉल सुरक्षित
कराए हैं। संयुक्त आयुक्त उद्योगों
अनुसार, यह भागीदारी दर्शाती है कि
शहर की नई पीढ़ी अब सिर्फ
बिचौलियों या बड़े घरानों पर निर्भर
रहने के बजाय सीधे वैश्विक आपूर्ति
श्रृंखला (ग्लोबल सप्लाई चैन) का
हिस्सा बनने को तैयार है। इसके साथ
ही, हॉल नंबर 15 (रेगुलर

एक्सपोर्टर्स और थ्रू-
के साथ-साथ विस्तरा
ऑर्डर हल
एक्सपोर्टर्स
परिदृश्य
विदेशी
रिटेल न
बिचौलियों
जिससे
दूरतक
पूरा और
शहर के
इकाइयों
मिलने
कारिगरे
अवसर

एक्सपोर्ट्स) में मुरादाबाद के 14 बड़े और स्थापित निर्यातक विदेशी बायर्स के साथ पहले से चल रहे अनुबंधों को विस्तार देंगे और बड़े वॉल्यूम के ऑर्डर हासिल करेंगे। इस अंतराष्ट्रीय एक्सपो से मुरादाबाद के आर्थिक परिदृश्य को बड़ा लाभ पहुंचेगा। सीधे विदेशी बायर्स और अंतराष्ट्रीय रिटेल चेस से जुड़ने से बीबीसी के बिचौलियों का कमीशन खत्म होगा, जिससे कारखानों से लेकर जमीनी दस्तकारों तक को अपने उत्पादों का पूरा और उचित मूल्य मिल सकेगा। शहर के छोटे कारखानों और ढलाई इकाइयों को नए एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलने से स्थानीय स्तर पर हजारों कारीगरों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

मुद्रक, प्रकाशक, स्वामी, सैफुल्लाह सिद्दीकी द्वारा आरडी प्रिंटिंग एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए-24, सेक्टर-08, नोएडा (यूपी), से छपवा कर एन-81, बटला हाउस, जामिया नगर पुलिस स्टेशन, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025 से प्रकाशित किया। सर्वाधिकार सुरक्षित, किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा। (संपादक- सैफुल्लाह सिद्दीकी)